राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी

पूर्वांचल का सतत विकास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक पहल

मुद्दे, रणनीति एवम् भावी दिशा

10-12 दिसम्बर, 2020

विवरणी

आयोजक:

नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर

www.ddugu.ac.in

राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी

पूर्वांचल का सतत विकासः मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा

(अवधिः 10–12 दिसम्बर, 2020)

आयोजक

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

संदेश

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पूर्वान्चल विकास बोर्ड के माध्यम से नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनॉक 10 से 12 दिसम्बर, 2020 की अवधि में आयोजित ''पूर्वान्चल का सतत विकासः मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा'' विषयक राष्ट्रीय स्तर के तीन दिवसीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी की विभिन्न गतिविधियों तथा इसमें प्रस्तुत शोध पत्रों एवं विचार–विमर्श के आधार पर नियोजन विभाग द्वारा डाक्यूमेन्ट (विवरणी) का प्रकाशन किया जा रहा है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उ0प्र0 सरकार पूर्वान्चल क्षेत्र के समग्र विकास के लिये कृत संकल्पित है। इस सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र की प्रगति के लिये अनेक योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास की लाइफ–लाईन बनने जा रही पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना का कार्य तेज गति से जारी है। इस प्रकार पूर्वान्चल के हितार्थ किये जा रहे विभिन्न प्रयासों से क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास होगा तथा युवाओं को रोजगार मिलेगा।

पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। यह अत्यन्त सराहनीय है कि पूर्वान्चल के सम्पूर्ण विकास के लिये सम्यक विचारोपरान्त यह डाक्यूमेन्ट तैयार किया गया है। मुझे आशा है कि यह डाक्यूमेन्ट पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास से जुड़े सभी लोगों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

डाक्यूमेन्ट के उद्देश्यपरक प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(योगी आदित्यनाथ)

संदेश

नरेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष
पूर्वान्चल विकास बोर्ड, उ0प्र0

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु परामर्शी संस्था के रूप में पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के गठन के उद्देश्यों के अनुरूप इस बोर्ड की विभिन्न बैठकों में हुये निर्णयानुसार पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों से सम्बन्धित 13 समितियों का गठन किया गया, जिसमें बोर्ड के मा0 पदाधिकारीगण, सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण एवं ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शिक्षाविद् सम्मिलित हैं। इन समितियों द्वारा निरन्तर चिंतन तथा बैठकें कर पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु स्टेटस पेपर तैयार किये गये। इसी क्रम में पूर्वान्चल विकास बोर्ड के माध्यम से पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनॉक 10 से 12 दिसम्बर, 2020 को **"पूर्वान्चल का सतत विकासः मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा"** विषयक राष्ट्रीय स्तर का तीन दिवसीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर में आयोजित किया गया।

वेबिनार में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, देश–विदेश के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविदों आदि द्वारा आनलाईन/व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग कर पूर्वान्चल के विकास हेतु शोध पत्र/विचार प्रस्तुत किये गये। वेबिनार में प्रतिभागियों द्वारा विविध सत्रों में किये गये प्रस्तुतीकरण तथा विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा यह डाक्यूमेन्ट (विवरणी) तैयार किया गया है। मेरा मत है कि इस महत्वपूर्ण डाक्यूमेन्ट के आधार पर पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु प्रदेश के सम्बन्धित विभागों को आगामी वर्षों में दूरगामी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

मैं इस विशिष्ट कार्य में अथक प्रयास करने के लिये पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सम्मानित साथियों, श्री के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 तथा श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस महत्वपूर्ण आयोजन में निरन्तर योगदान तथा प्रतिबद्धता हेतु कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रशासनिक विभागों तथा शिक्षाविदों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(नरेन्द्र सिंह)

संदेश

डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु"
उपाध्यक्ष
पूर्वान्चल विकास बोर्ड, उ0प्र0

पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु परामर्शी संस्था के रूप में पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड द्वारा विभिन्न बैठकें आयोजित कर पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु संस्तुतियां प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों से सम्बन्धित समितियों का गठन भी किया गया।

इस क्रम में पूर्वान्चल विकास बोर्ड के माध्यम से पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनॉक 10 से 12 दिसम्बर, 2020 की अवधि में **"पूर्वान्चल का सतत विकासः मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा"** विषयक राष्ट्रीय स्तर का तीन दिवसीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर में आयोजित किया गया। वेबिनार में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, देश–विदेश के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविदों आदि द्वारा आनलाईन/व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग कर पूर्वान्चल के विकास हेतु शोध पत्र/विचार प्रस्तुत किये गये।

वेबिनार में प्रतिभागियों द्वारा विविध सत्रों में किये गये प्रस्तुतीकरण तथा विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा यह डाक्यूमेन्ट (विवरणी) तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह डाक्यूमेन्ट पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु प्रदेश के सम्बन्धित विभागों को आगामी वर्षों में दूरगामी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

मैं इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिये पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सम्मानित साथियों, श्री के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन तथा कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रशासनिक विभागों तथा शिक्षाविदों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु")

संदेश

साकेत मिश्र
सलाहकार,
पूर्वान्चल विकास बोर्ड, उ0प्र0

पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनॉक 10 से 12 दिसम्बर, 2020 की अवधि में **''पूर्वान्चल का सतत विकासः मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा''** विषयक राष्ट्रीय स्तर का तीन दिवसीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर में आयोजित किया गया।

वेबिनार में प्रतिभागियों द्वारा विविध सत्रों में किये गये प्रस्तुतीकरण तथा विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा यह डाक्यूमेन्ट (विवरणी) तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह डाक्यूमेन्ट पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु प्रदेश के सम्बन्धित विभागों को आगामी वर्षों में दूरगामी निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा।

मैं इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिये पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सम्मानित साथियों, श्री के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन तथा कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रशासनिक विभागों तथा शिक्षाविदों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(साकेत मिश्र)

राजेन्द्र कुमार तिवारी
आई.ए.एस

लोक भवन
लखनऊ- 226001
ई-मेलः csup@nic.in
फोनः (0522) 2289212, 2289296 (का.)
(0522) 2239461, 2237299 (आ.)
(0522) 2239283 (फैक्स)

"संदेश"

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में प्रदेश को चार आर्थिक सम्भागों यथा–पश्चिमी, पूर्वी, केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इन सम्भागों की जहाँ एक ओर अपनी–अपनी विशिष्टतायें हैं, वहीं दूसरी ओर इन सम्भागों की अपनी–अपनी समस्यायें भी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्वान्चल सम्भाग के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतया परामर्शी संस्था के रूप में पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को त्वरित गति प्रदान करने के सम्बन्ध में पूर्वान्चल विकास बोर्ड के माध्यम से नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर का तीन दिवसीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर में किया गया।

वेबिनार–सह–संगोष्ठी का उदघाटन तथा समापन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस वेबिनार–सह–संगोष्ठी के विविध तकनीकी सत्रों में प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगणों, विभिन्न विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी उद्यमों के प्रतिनिधियों द्वारा उत्साहपूर्वक ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया गया तथा पूर्वान्चल क्षेत्र के समग्र एवं संतुलित विकास के लिये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा– प्राथमिक, विनिर्माण, सेवा, सामाजिक एवं जल क्षेत्र के साथ ही विविध विशेष सत्रों से सम्बन्धित शोध पत्र, उद्बोधन व मन्तव्य प्रस्तुत किये गये।

संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में हुये विचार–विमर्श एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं नियोजन विभाग द्वारा यह डॉक्यूमेन्ट (विवरणी) तैयार किया गया है, जिससे निश्चय ही पूर्वान्चल के विकास के लिये विभिन्न विकास विभागों को आगामी वर्षों में निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

यह संगोष्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं उनके मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई, जो निःसन्देह पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में कारगर एवं सहायक सिद्ध होगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगणों का आभारी हूँ, जिन्होंने गोष्ठी में अपने सारगर्भित एवं विषयपरक उद्बोधन से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। संगोष्ठी को

सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने तथा डॉक्यूमेन्ट (विवरणी) तैयार करने के लिये मैं विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के शिक्षाविदों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगोष्ठी में शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य गणमान्य महानुभावों के मंथन, चिन्तन एवं उद्‌बोधन के फलस्वरूप तैयार किये गये इस डॉक्यूमेन्ट (विवरणी) से पूर्वान्चल क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रदेश के विभागों को रणनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

प्राक्कथन

कुमार कमलेश
आई0ए0एस0
अपर मुख्य सचिव
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों में आता है। इसे चार आर्थिक सम्भागों यथा–पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड में विभाजित किया गया है। पूर्वान्चल क्षेत्र की विकास सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है, जिसके क्रम में इस क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतया परामर्शी संस्था के रूप में पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

पूर्वान्चल विकास बोर्ड की मण्डलवार विविध बैठकों में हुये विचार–विमर्श के आधार पर पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु बोर्ड द्वारा विभिन्न सेक्टरों यथा–कृषि, पशुपालन, जल प्रबन्धन, उद्योग, कौशल विकास आदि से सम्बन्धित 13 समितियों का गठन किया गया। इसके साथ ही उच्च स्तरीय निर्णयानुसार पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में पूर्वान्चल विकास बोर्ड के माध्यम से नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में **"पूर्वान्चल का सतत विकासः मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा"** विषयक राष्ट्रीय स्तर का तीन दिवसीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर में आयोजित किया गया।

वेबिनार का उद्घाटन श्री योगी आदित्यनाथ, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ, जिसके दौरान विशिष्ट अतिथिगणों में डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, उ0प्र0 सरकार, श्री रवि किशन, मा0 सांसद, श्री नरेन्द्र सिंह एवं डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु", मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड एवं बोर्ड के मा0 सदस्यगण उपस्थित रहे। संगोष्ठी का समापन वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से श्री योगी आदित्यनाथ, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 द्वारा सम्पन्न हुआ।

वेबिनार में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा– प्राथमिक, विनिर्माण, सेवा, सामाजिक एवं जल क्षेत्र के साथ ही विविध विशेष सत्रों से सम्बन्धित ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रीगणों, विभिन्न विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी उद्यमों के प्रतिनिधियों द्वारा उत्साहपूर्वक आनलाईन/व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया गया तथा शोधपत्रों एवं विचार–विमर्श के माध्यम से पूर्वान्चल के समग्र विकास के सन्दर्भ में अपने प्रस्तुतीकरण/उद्बोधन/मन्तव्य प्रस्तुत किये गये।

वेबिनार के विविध सत्रों में किये गये प्रस्तुतीकरण तथा विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा यह डाक्यूमेन्ट (विवरणी) तैयार किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेन्ट है, जिसके आधार पर पूर्वान्चल सम्भाग के विकास हेतु आगामी वर्षों में दूरगामी निर्णय लिये जाने में सहायता मिलेगी।

मैं इस वेबिनार के विभिन्न तकनीकी सत्रों में उपस्थित मा0 मंत्रीगणों, पूर्वान्चल विकास बोर्ड के मा0 पदाधिकारियों, तकनीकी सत्रों से सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों तथा अन्य मा0 जनप्रतिनिधियों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सहयोग एवं अथक परिश्रम के कारण ही यह वेबिनार सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा उनकी टीम के विषय विशेषज्ञों का विशेष आभारी हूँ, जिनके निरन्तर सहयोग एवं समर्पण के द्वारा ही यह वेबिनार सम्पन्न हो सका है।

मैं मुख्य रूप से आर्थिक सलाहकार, श्री के0वी0 राजू, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार का विशेष आभारी हूँ, जिनके निरन्तर तकनीकी सहयोग एवं कुशल मार्ग निर्देशन में यह वेबिनार सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका। इसके अतिरिक्त मैं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव, श्री आमोद कुमार एवं विशेष सचिव, श्री आर0एन0एस0 यादव को उनके समर्पित भावना से दक्षतापूर्वक दायित्व निर्वहन के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री विजय कुमार अग्रवाल, निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग एवं उनकी टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वेबिनार के सभी चरणों तथा तैयार किये गये डाक्यूमेन्ट में निरन्तर किये गये परिश्रम एवं प्रतिबद्धता की मैं प्रशंसा करता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि वेबिनार के आधार पर तैयार किया गया यह डाक्यूमेन्ट निश्चय ही प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों को पूर्वान्चल के समग्र विकास हेतु रणनीति तैयार करने में सहायक होगा।

(कुमार कमलेश)

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	राष्टोय वेबिनार का संक्षिप्त परिचय	1
2	कार्यकारी सारांश	7
3	उद्घाटन सत्र	12
4	प्राथमिक क्षेत्र	15
5	विनिर्माण क्षेत्र	23
6	सेवा क्षेत्र	31
7	सामाजिक क्षेत्र	39
8	जल क्षेत्र	45
9	विशेष सत्रः सामूहिक संगठनों से संबंधित	51
10	विशेष सत्रः पूर्वांचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन (स्पेशल पैकेज फॉर पूर्वांचल)	52
11	विशेष सत्रः बैंकिंग क्षेत्र	53
12	विशेष सत्रः औद्योगिक क्षेत्र	54
13	विशेष सत्रः खेल	56
14	समापन सत्र	57
15	राष्ट्रीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	59
परिशिष्ट–1	माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन	67
परिशिष्ट–2	वेबिनार में उपस्थित मा0 मंत्रीगण	74
परिशिष्ट–3	वेबिनार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि/प्रशासनिक अधिकारी/शिक्षाविद्	75

राष्टोय वेबिनार का संक्षिप्त परिचय

पूर्वान्चल

उत्तर प्रदेश के कुल 18 मण्डलों एवं 75 जनपदों में से 8 मण्डल और 28 जनपदों वाला पूर्वी क्षेत्र पूर्वान्चल की अनूठी विस्तृत पट्टी है जो 23 अंश 51' उत्तर से 28 अंश 30' उत्तर तथा 81 अंश 31' पूर्व से 84 अंश 39' पूर्व तक फैली है। यह उत्तर प्रदेश के इन्द्रधनुषी भू–भाग को प्रस्तुत करता है जहॉ बहुरंगी भारतीय संस्कृति अनन्तकाल से पुष्पित–पल्लवित होती रही है। भिन्न–भिन्न भौगोलिक विस्तार एवं विविधतापूर्ण संस्कृति से समृद्ध पूर्वान्चल अनगिनत पवित्र पुण्य स्थल एवं तीर्थ स्थलों से परिपूर्ण है जहॉ तीज–त्यौहारों, भोजपुरी की मिठास तथा अनेकानेक व्यजनों की सुवास इसकी श्रीवृद्धि करते है। भारत के पयर्टन मानचित्र पर पूर्वान्चल का विशिष्ट स्थान है। मौसम सामान्यतया उष्णता एवं शुष्क शीतलता लिए होता है। यद्यपि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से अर्धशुष्क है। यहॉ कृषि लघु एवं अल्प जोत वाली है और नियमित रूप से आने वाली बाढ़, सूखे एवं मृदा लवणता से प्रभावित है। वर्ष 2017 में नवगठित सरकार द्वारा लागू की गयी उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के निवेश आकर्षित करने एवं औद्योगिक उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से बल देती है। मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से प्रदेश में निजी औद्योगिक उद्यमों, सेज, एकीकृत विनिर्माण मूल्यों एवं पूर्वान्चल के उन्नयन के लिए औद्योगिक गलियारों को प्रोत्साहित करने के अथक प्रयास, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के युद्ध स्तर पर संचालन के तौर पर फलीभूत हुए हैं।

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

राज्य स्तर पर बनायी जाने वाली योजना राष्ट्र के साथ–साथ राज्य के समुचित एवं त्वरित विकास के दोहरे हितों को साधने का मन्तव्य रखती है। इसका अर्थ है कि राज्य स्तर के नियोजक को न केवल राज्य के लक्ष्यों, प्राथमिकताओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करने में एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए अपितु राष्ट्रीय नीतियों एवं उद्देश्यों के निरूपण में भी सहभागिता करनी चाहिए जिससे राज्य के सम्पूर्ण विकास का वातावरण तैयार हो सके। उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर योजनाओं का निरूपण बहुस्तरीय पारस्परिक संवाद सत्रों एवं युक्तपूर्ण विकास की लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाय। कार्यान्वयन की दृष्टि से एक योजना परस्पर सम्बन्धित कार्यक्रमों/परियोजनाओं/प्रणालियों का संकलन है जो स्थानिक, संस्कृतियों एवं उपयुक्त सामयिक अनुक्रमण के माध्यम से वांछित परिणामों को अर्जित करने का उद्देश्य रखती है। योजना निरूपण, व्यवस्थित विश्लेषण, प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण एवं

अन्वेषण विकल्पों की उपयुक्तता एवं नवीन उपागमों के प्रयोग पर आश्रित है। नियोजन एक बहुविषयी कार्य है जो तकनीकी विशेषज्ञों, भूगोलवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों, समाजशास्त्रियों, प्रबन्ध विशेषज्ञों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, वास्तुविदों आदि की समान सहभागिता की मॉग करता है। साथ ही साथ यह संवेदनाओं आमतौर पर लोगों की आवश्यकता आधारित प्राथमिकताओं और विशेष तौर पर विशिष्ट कार्यक्रमों के लाभार्थियों की प्राथमिकताओं को लेकर विश्वसनीय सूचना के एक बेहद सुविचारित एवं व्यवस्थित प्रवाह की भी मांग करता है। उपरोक्त सारे परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निःसन्देह आवश्यक है कि नियोजन एवं क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया एक दक्ष एवं सक्षम मानव संसाधन से सम्पन्न हो।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 सितम्बर, 1957 के कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय एवं शिक्षा संकाय के साथ संचालित होना प्रारम्भ हुआ। विश्वविद्यालय की अकादमिक संस्कृति अध्ययन एवं शोध की विविध परम्पराओं की पारस्परिक विनिमयन से विकसित हुई। अपने प्रतीक चिन्ह में वर्णित सूत्र वाक्य का निरन्तर पालन करते हुए विश्वविद्यालय ज्ञान के उन्मुक्त अन्वेषण में सदैव संलग्न रहते हुए नवोन्मेष एवं उत्कृष्टता अर्जित करने में अनवरत दृढ़ आस्था का प्रदर्शन करता रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वर्तमान पीढ़ी में अध्येतायों का एक प्रतिष्ठित समुदाय है जिन्होंने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। विश्वविद्यालय की परिकल्पना एवं इसके स्थापना के लिए प्रयत्नशील एवं समर्पित लोगों के चलते पूर्वान्चल और इसके आस–पास के लोगों की उच्च शिक्षा तक सुगम पहुॅच सम्भव हो सकी। विश्वविद्यालय एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जो रोजगार एवं शोध के बेहतर अवसरों के सृजन की कल्पना करता है। लगभग पचास नये बाजारोन्मुख पाठयक्रम प्रस्तावित कर विश्वविद्यालय पूर्वान्चल एवं आसपास के क्षेत्रों में उद्यमिता विकास की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए कमर कस चुका है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय शोध एवं उद्भवन केन्द्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के माध्यम से विदेशी छात्रों एवं शोधार्थियों को आकर्षित करने के लिए दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ा चुका है। उत्कृष्टता के विभिन्न नवीन केन्द्रों एवं खेल सम्बन्धी गतिविधियों की महत्वाकांक्षी परिकल्पना की गयी है जो संस्था को एक नया आकार प्रदान करती है।

राष्ट्रीय वेबिनार एवं संगोष्ठो

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार जो उत्तर प्रदेश राज्य एवं विशिष्ट तौर पर पूर्वान्चल के समग्र विकास योजना के व्यावहारिक पक्षों के निरूपण की दृष्टि से कार्य करता है के द्वारा अध्येताओं, अन्वेषकों, पेशेवरों, व्यवसायियों, राजनेताओं, अधिकारियों और आमजनों

के साथ एक ही मंच पर विचार विनिमय के लिए वृहद स्तर पर यह वेबिनार आयोजित की गयी है। कोविड–19 काल में मिश्रित प्रणाली से निर्बाध रूप से चलने वाले एक राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी की संकल्पना के माध्यम से यह सम्भव किया गया है। दिनॉक 10 से 12 दिसम्बर, 2020 तक आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी के दौरान दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित विविध संगोष्ठी कक्षों में उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों को प्रतिनिधित्व करने वाले अलग–अलग विषयों पर केन्द्रित कई समान्तर सत्र आयोजित हुये, जिनमें अपने–अपने क्षेत्रों के सैकड़ों विशेषज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वान्चल क्षेत्र के त्वरित विकास एवं संवर्धन के व्यावहारिक पक्षों पर एक सुचिन्तित परिचर्चा की गयी। मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी समाज के समग्र विकास हेतु पूर्वान्चल के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नही छोड़ना चाहते हैं। हम उन सारे शिक्षकों व छात्रों, प्रशासकों व व्यवसायियों, राजनेताओं व समाज सेवियों से हाथ मिलाने को उत्सुक हैं जो इन सपनों को साकार करने में योगदान देने को तत्पर है इसी हेतु हमारे विशेष सत्र भी संचालित हुये हैं।

पूर्वान्चल का औद्योगिक विकास

इस सत्र का आयोजन इस विचार पर आधारित है कि पूर्वान्चल में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को लेकर शिक्षाविदों, शोधार्थियों तथा उद्यमियों के बीच वैविध्यपूर्ण, बुद्धयोत्तेजक अन्तःक्रिया ऐसे सभी विचारों के क्रमिक उर्वरण व विकास के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन कर सके जिससे कि समस्त सम्भावित पक्षों तथा उनके प्रस्ताव को बल प्रदान कर प्रतियोगी परियोजनाएं उद्घाटित हो। ऐसी परियोजनाएं ही पूर्वान्चल तथा उत्तर प्रदेश के त्वरित व भावी विकास में महती भूमिका अदा कर सकती है। अतः सभी पक्षकारों को एक साथ एक ही मंच पर उपस्थित होकर परस्पर विचार–विमर्श कर भावी रणनीति का मार्गदर्शन ही इस सत्र का मुख्य लक्ष्य रखा गया।

पूर्वान्चल के लिये विशेष प्रोत्साहन

"उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017" के प्रारम्भ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नियोजन का परिदृश्य बदला है। प्रस्तुत सम्मेलन व सत्र में उक्त तथा अन्य ऐसे ही नियोजक, उत्पादक और उद्यमी की बीच सफल रिश्ता कायम करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने सम्बन्धी सम्भावित योजनाओं व नीतियों पर परिचर्चा की गयी।

बैंकर्स सम्मेलन

व्यवसाय करने की सरलता व सुविधा उद्यमिता विकास की नींव है। उद्यमिता विकास की मार्ग पर बैकों द्वारा दिये जाने वाला वित्तीय सहयोग ही वास्तव में प्रथम सहयोग है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि बैंकर्स और उद्यमी इस महती सहभागिता को सफल बनाने के लिए एक–दूसरे को समझें और जानें। प्रस्तुत सम्मेलन दोनों पक्षों को एक मेज पर लाने का प्रयास था जहाँ जीवनपर्यन्त रिश्ता स्थापित होने के पूर्व आपसी सन्धि क्रम का माहौल तैयार हो।

विशिष्ट संगठित समूह (स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पाद संगठन, गैर सरकारी संस्थाएं)

किसानों, कलाकारों, शिल्पकारों व ऐसे अन्य पेशेवरों के समूह, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पाद संगठन तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पूर्वान्चल के विकास में अद्वितीय भूमिका का वहन करने में सक्षम है परन्तु "कैसे" यही जानना इस सत्र का मुख्य उद्देश्य रखा गया।

तकनीकी सत्र एवं समन्वयक

तकनीकी सत्र	उ0प्र0 शासन समन्वयक	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समन्वयक	सम्बन्धित नोडल विभाग
प्राथमिक क्षेत्र	डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	• प्रो0 अजय सिंह (प्राणी विज्ञान), संयोजक • डा0 स्मृति मल (वनस्पति विज्ञान), सह संयोजक	कृषि, कृषि विपणन, कृषि निवेश व्यापार एवं निर्यात, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण, रेशम, सहकारिता, मत्स्य, पशुधन, दुग्ध विकास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, वन एवं वन्य जीव
विनिर्माण क्षेत्र	• श्री आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। • श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उ0प्र0शासन।	• प्रो0 आलोक गोयल (अर्थशास्त्र), संयोजक • डा0 प्रतिमा जायसवाल (वाणिज्य),सह संयोजक	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज, पर्यावरण, भूतत्व एवं खनिकर्म, राजस्व, आवास एवं दैवीय आपदा राहत
सेवा क्षेत्र	श्री मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग,	• प्रो0 मनीष मिश्रा (इलेक्ट्रानिक्स), संयोजक	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, पर्यटन, संस्कृति, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल

	उ0प्र0 शासन।	• डा0 राजू गुप्ता (अर्थशास्त्र), सह–संयोजक	विकास, परिवहन, आवास एवं शहरी नियोजन, संस्थागत वित्त।
सामाजिक क्षेत्र	• श्री अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। • श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	• प्रो0 आर0पी0 सिंह (वाणिज्य), संयोजक • डा0 पवन कुमार (समाजशास्त्र), सह–संयोजक	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, सभी आई0सी0ए0आर0 इन्स्टीट्यूट, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, शोध एवं विकास संस्थान, स्वयंसेवी संगठन, सम्बन्धित विभागों द्वारा चिन्हित अन्य संस्थायें/व्यक्ति
जल क्षेत्र	श्री टी0 वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन	• प्रो0 उमेश यादव (भौतिक विज्ञान), संयोजक • डा0 अंशु गुप्ता (वाणिज्य), सह–संयोजक	सिंचाई एवं जल संसाधन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, नगर विकास
विशेष सत्रः औद्योगिक विकास	श्री आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	प्रो0 धनन्जय कुमार, मनोविज्ञान विभाग	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन
विशेष सत्रः पूर्वान्चल के लिए विशेष प्रोत्साहन	श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	प्रो0 एस0वी0 पाठक, वाणिज्य विभाग	सभी सम्बन्धित विभाग
विशेष सत्रः बैंकर्स सम्मेलन	• श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन • श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0 सरकार	प्रो0 उमा श्रीवास्तव, गणित एवं सांख्यिकीय विभाग	संस्थागत वित्त

विशेष सत्रः सामूहिक संगठनों से सम्बन्धित	श्री नवनीत कुमार सहगल, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन	प्रो0 अनुभूति दुबे, मनोविज्ञान विभाग	सभी सम्बन्धित विभाग

प्रतिभागियों का विवरण

इस कार्यक्रम में लगभग 1200 प्रतिभागियों ने चर्चा/पेपर प्रस्तुत किया। इसमें प्रमुख रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, केंद्रीय मा0 मंत्री, यू0जी0सी0 अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, मा0 उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कुलपति एवं पूर्व कुलपति, बैंकर्स, आई0आई0टी0/ सी0एस0आई0आर0/ आई0आई0एम0/एन0ए0आर0एम0 आदि के निदेशक सम्मिलित थे। संगोष्ठी में 23 देशों के साथ विभिन्न राज्यों के लोग 60 लिंक से जुड़े तथा लगभग 25 हजार हिट सोशल मीडिया पर संगोष्ठी को मिले।

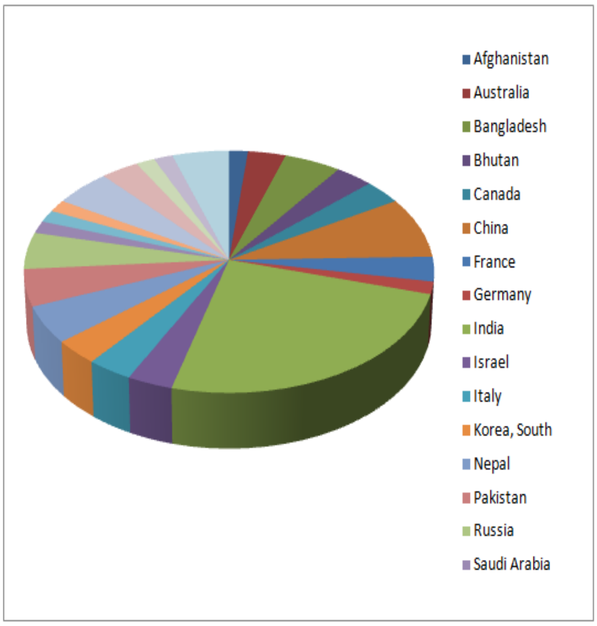

लिंक–हिट्स का देश–वार वितरण

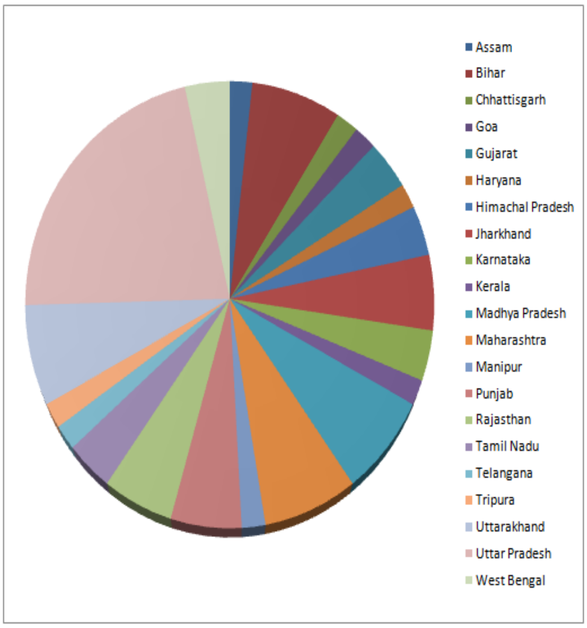

लिंक–हिट्स का प्रदेश–वार वितरण

कार्यकारी सारांश

- प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु **''पूर्वान्चल का सतत विकासः मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा''** विषयक तीन दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी का आयोजन दिनॉक 10–12 दिसम्बर, 2020 की अवधि में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

- श्री योगी आदित्यनाथ जी, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा दिनॉक 10 दिसम्बर, 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में इस राष्ट्रीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया तथा दिनॉक 12 दिसम्बर, 2020 को समापन समारोह में आर्शीवचन प्रदान किये गये। इस वेबिनार में मा0 मंत्रीगण/जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, अकादमिक प्रबंधकों, बैंकरों, निवेशकों, किसानों, शिक्षकों और छात्रों ने एक साथ भाग लिया और पूर्वांचल के विकास के रोडमैप को तैयार करने में अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किये।

- राष्ट्रीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी की पूरी अवधारणा को पांच क्षेत्रों – प्राथमिक, सामाजिक, सेवा, विनिर्माण एवं जल के साथ–साथ विशेष सत्रों यथा–औद्योगिक विकास, बैंकर्स मीट, विशेष संगठित समूह, पूर्वांचल के लिए विशेष पैकेज, खेलकूद आदि में विभाजित किया गया था। वेबिनार की अवधि में सभी सेक्टरों में कुल 56 सत्र आयोजित हुये।

- प्राथमिक **क्षेत्र** के अन्तर्गत कुल 9 तकनीकी सत्रों में हुये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आयेः–

  - कृषि एवं इससे जुड़ी श्रम शक्ति पर फोकस करना।
  - हर्बल उत्पादों को अपनाया जाना।
  - महाराष्ट्र राज्य की तरह प्याज की खेती कराना।
  - खाड़ी देशों में हरी मटर, मिर्ची के निर्यात के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि कराना।
  - मत्स्य पालन में आ रही विविध समस्याओं यथा– तालाबों की खराब स्थिति, जल संसाधन का कम उपयोग आदि को दूर करना।
  - पूर्वांचल के 11 जनपदों को आई0आई0ए0आर0 के सहयोग से "काला नमक चावल'' योजना से आच्छादित कर निर्यात प्रोत्साहन पर बल देना।
  - गुजरात पैटर्न पर दुग्ध उद्योग का विकास किये जाना।

- प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) को नई सोच, तकनीकी एवं पारदर्शिता के साथ सुदृढ़ करते हुए कप्यूटराइजेशन कर बहुआयामी बनाने तथा एफ0पी0ओ0 को मजबूत करने पर जोर दिया जाना।
- आर्गेनिक खेती की सहायता से पूर्वान्चल को उत्पादन, विपणन तथा निर्यात सेक्टर में "हब" बनाने पर बल दिया जाना।
- "खुशबूदार फसलों (ऐरोमेटिक क्राप्स)" की खेती से कृषकों की आय में वृद्धि किया जाना।
- बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पौधों की प्रजाति पर फोकस करने पर बल देना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में पशु उत्पादन कम होने के कारण इसको प्रोत्साहन देना तथा टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा पर बल देना।
- पोल्ट्री व्यवसाय के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर की इकाई बढ़ाने, पशुओं का बीमा कराने तथा चारे की समस्या दूर करने हेतु चारागाह के क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार करना।

- **विनिर्माण क्षेत्र** के अन्तर्गत कुल 9 तकनीकी सत्रों में हुये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आयेः–

  - पूर्वी क्षेत्र के जनपदों यथा– अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मिर्जापुर के उत्पादों को प्रोत्साहन तथा निर्यात में बढ़ावा दिये जाने पर बल देना।
  - बायो, मेडिकल एवं कंस्ट्रक्शन वेस्ट के उपयोग हेतु वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेन्ट पर बल देना।
  - फल एवं सब्जियों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को एम0एस0एम0ई0 के अंतर्गत स्थापित किये जाना।
  - ''वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'' के अंतर्गत तैयार किये जा रहे विविध उत्पादों यथा–हैण्डलूम, कारपेट, हैण्डीक्राफ्ट, हार्डवेयर इत्यादि की पैकेजिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी मेन्टेन करने हेतु कामन फैसेलिटीज सेन्टर/वेयर हाउस स्थापित किये जाने पर विचार करना।
  - पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अतिरिक्त सोलर ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया जाना।
  - पूर्वान्चल क्षेत्र में एअर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किये जाना।
  - पूर्वान्चल में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए रोड नेटवर्क का निर्माण किया जाना।
  - लोक निर्माण विभाग को छोड़कर सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्य निर्माण एजेन्सियों द्वारा लोक निर्माण के मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण कार्य कराये जाने की व्यवस्था/नीति बनाने पर विचार करना।

- एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत उद्यम स्थापित किये जाने हेतु शिक्षित व कुशल व्यक्तियों को आधुनिक तकनीक, संसाधन व अन्य व्यवस्थाओं पर जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होना।

- **सेवा क्षेत्र** के अन्तर्गत कुल 9 तकनीकी सत्रों में हुये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आयेः–

    - पूर्वान्चल सहित उत्तर प्रदेश में वर्तमान रोजगार की स्थिति मुख्य रुप से कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में होने के दृष्टिगत भविष्य में कौशल विकास हेतु आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, इन्टरनेट आफ थिंग्स, ब्लाक चेन, साईबर सिक्योरिटी, 5जी कम्युनिकेशन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाये जाने पर विचार करना।
    - महिलाओं के विकास हेतु उन्हें तकनीकी शिक्षा दिलाये जाने पर बल देना।
    - अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी को ''गोल्डेन ट्राईऐंगिल स्पीरिचुअल'' टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाना।
    - पूर्वान्चल में राष्ट्रीय धरोहरों के साथ पंचकोसी यात्रा, सलखन फासिल पार्क (सोनभद्र) तथा प्रागैतिहासिक शैल चित्र, लखनिया पेंन्टिग आदि के संरक्षण की आवश्यकता होना।
    - अधिग्रहित भूमि के सुनिश्चित उपयोग, भूमि सम्बन्धित विवादों का निपटारा, किरायेदारों के सम्बन्ध में लीज का पुर्नमूल्यांकन, प्लास्टिक के उन्मूलन, नगर निगम क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण एवं तत्सम्बन्धी जैविक खेती जैसे नवोन्मेषी विचारों को अपनाया जाना।
    - वाहन निरीक्षण कार्यक्रम, गाड़ी फिटनेस सेन्टर एवं ड्राईवर फिटनेस को प्रोत्साहित करना।
    - दिहाड़ी मजदूरों को निकटस्थ बाजारों में नियमित रोजगार न मिल पाने के परिप्रेक्ष्य में लेबर हायर एप्लिकेशन को विकसित करने पर बल दिया जाना।

- **सामाजिक क्षेत्र** के अन्तर्गत कुल 9 तकनीकी सत्रों में हुये विचार–विमर्श/ प्रस्तुतीकरण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आयेः–

    - वेक्टर और जल जनित रोगों और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।
    - SARS, COVID-19 और उनके नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता कराना।
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

- एम0बी0बी0एस0 जैसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने स्तर से बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- स्मार्ट क्लासेस सिस्टम तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों पर छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु बल दिया जाना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में शैक्षिक सुधारों को लागू करने तथा सकल नामांकन दर को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में छात्र–शिक्षक अनुपात में सुधार करना।
- महिला साक्षरता दर में वृद्धि हेतु प्रयास करना।

- **जल क्षेत्र** के अन्तर्गत कुल 9 तकनीकी सत्रों में हुये विचार–विमर्श/ प्रस्तुतीकरण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आयेः–

  - गंडक, शारदा सहायक प्रणाली में बनी हुई संरचनाओं की पुनरोद्धार की आवश्यकता होना।
  - रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन पर बल देना।
  - जल संरक्षण नीति की आवश्यकता।
  - बाढ़ के प्रभाव को कम करने हेतु उपाय कराना।
  - पुरानी पाइप लाइनों से जल के ह्रास होने के परिप्रेक्ष्य में इनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता।
  - भूमिगत जल का दोहन प्रबन्धन।
  - भूजल में आर्सेनिक की समस्या तथा भूजल स्तर में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में पूर्वान्चल के समस्त विकासखण्डों में मल्टीपल मानीटरिंग नेटवर्क की आवश्यकता होना।
  - औद्योगिक कचरे के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था कराना।
  - गंगा नदी के किनारे दाह संस्कार स्थलों को विकसित कराना।
  - पूर्वान्चल में बाढ़ एवं सूखे की समस्या के निदान हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता होना।
  - वाटर क्वालिटी टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता।
  - अटल मिशन फार रेजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन की गाइड लाइन्स का पालन कर अप्रेजल और गैप असेसमेन्ट को ज्ञात करके इसके निदान हेतु स्थानीय लोगों की सहभागिता की आवश्यकता।
  - ''इन्टीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट'' में ब्राजील और फ्रांस के माडल को एडाप्ट करने की आवश्यकता पर विचार करना।

- इरीगेशन मैनेजमेन्ट पर फ्रांस के माडल को एडाप्ट करने की आवश्यकता पर विचार करना।

- **विशेष सत्रों यथा– औद्योगिक विकास, बैंकर्स मीट, विशेष संगठित समूह, पूर्वांचल के लिए विशेष पैकेज, खेलकूद** आदि में हुये विचार–विमर्श/ प्रस्तुतीकरण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आयेः–

  - टेराकोटा आइटम को विभिन्न स्थलों तक ऑनलाईन पहुंचाने के लिये पैकेजिंग की समस्या के निराकरण पर विचार करना।
  - छोटे एवं मध्यम उद्योगों के कारीगरों के जीवन में व्यापक आर्थिक एवं सूक्ष्म स्तर की समस्याओं का समाधान।
  - आधारभूत संरचनागत प्रबन्धन में 3D मैपिंग और जी0आई0एस0 तकनीक के उपयोग पर विचार करना।
  - स्वयं सहायता समूहों का बैंकों द्वारा खाता खोले जाने, बैंकिग समिति बनाकर लोगों को साक्षात्कार के माध्यम से लोन देने पर बल देना।
  - किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्टार्टअप कार्यक्रम को डिजीटाइज करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता होना।
  - पारंपरिक उत्पादों के लिए नए डिजाइन विचारों को विकसित करने तथा स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की आवश्यकता।
  - 4 M's यानि मैन, मनी, मशीन और मार्केट का क्लस्टर बनाने की आवश्यकता।
  - 'रिवर्स माइग्रेशन' को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां और रणनीतियाँ।
  - उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कुशल मानव–संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधा की आवश्यकता।
  - अत्याधुनिक अनुसंधान, परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता।
  - पूर्वांचल को आई0टी0 हब के रूप में विकसित करना।
  - कई SEZs विकसित करने पर विचार करना।
  - विश्वविद्यालयों में खेल विभाग न होने, योग्य प्रशिक्षकों और शिक्षकों की भारी कमी तथा वित्तीय व्यवस्था का अभाव होने के परिप्रेक्ष्य में इनके निराकरण हेतु प्रयास करना।

उद्घाटन सत्र

- उद्घाटन सत्र का आयोजन दीक्षा भवन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में दिनॉक 10.12.2020 को सम्पन्न हुआ।
- उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, विशिष्ट अतिथि श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड तथा डा0 दया शंकर मिश्र "दयालु", मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड थे। मंच पर मा0 मुख्यमंत्री जी, दोनों मा0 उपाध्यक्ष, श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन तथा कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर मंचासीन रहे।
- उद्घाटन सत्र लगभग अपरान्ह 04:00 बजे से सायं 05:35 बजे तक संचालित हुआ।
- इस सत्र में सर्वप्रथम दीप प्रज्जवलन, राष्ट्रगीत एवं कुलगीत का प्रस्तुतीकरण आदि कार्यक्रम सम्पादित हुये। कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा मंचासीन मुख्य अतिथि एवं दोनों विशिष्ट अतिथियों को गुलाब पुष्प भेंटकर स्वागत किया गया। तदुपरान्त कुलपति महोदय ने उपस्थित विशिष्ट प्रतिभागियों यथा– डा0 महेन्द्र सिंह, जलशक्ति मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड, डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु", मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड, मा0 सांसद (श्री रविकिशन), महापौर, गोरखपुर, डा0 के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, श्री साकेत मिश्र, मा0 सलाहकार, पूर्वान्चल विकास बोर्ड, मा0 सदस्यगण, पूर्वान्चल विकास बोर्ड, मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का परिचय कराया।
- कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि लगभग 386 शोधपत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुये, जिसमें लगभग 70 पूर्ण पेपर तथा 204 "एब्सट्रेक्ट" सम्मिलित हैं। वेबिनार में अनेक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों यथा– हावर्ड विश्वविद्यालय, एम0आई0टी0 यूनिवर्सिटी आफ मेरीलैण्ड, यूनिवर्सिटी आफ मांटगोमरी, जॉन हॉकिंगस तथा अन्य अकेडमिक संस्थाओं व यू0के0, यू0एस0ए0 सहित पाँच से अधिक देशों से शोध पत्र प्राप्त हुये हैं। साथ ही वेबिनार के दौरान विभिन्न ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व यथा– प्रो0 डी0पी0 सिंह, अध्यक्ष,

यू0जी0सी0, श्री फ्रैंक इस्लाम, निवेश समूह के अध्यक्ष, यू0एस0, डा0 पंजाब सिंह, पूर्व डायरेक्टर जनरल, आई0सी0ए0आर0 आदि के वेबलिंक के माध्यम से जुड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

- तत्पश्चात डॉ0 दया शंकर मिश्र "दयालु'', मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड ने अपने सम्बोधन में प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास एवं विशिष्टताओं का जिक्र करते हुये प्राथमिक शिक्षा के उच्चीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करने आदि पर बल दिया।
- श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वान्चल विकास बोर्ड, उ0प्र0 ने उपस्थित विशिष्ट प्रतिभागियों तथा पूर्वान्चल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुये पूर्वान्चल क्षेत्र की समस्याओं पर तीन दिवस गहन विचार–विमर्श करने हेतु प्रेरित किया।
- मा0 मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुये यह कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत को अग्रणी देशों में नहीं गिना जाता था किन्तु आज सारी दुनिया भारत वर्ष से सीख प्राप्त कर रही है। वर्ष 2017 के पूर्व जो उ0प्र0 की धारणा देश /विदेश के जनमानस में थी, वह अब परिवर्तित हो रही है। हमें अपनी सोच को विस्तृत बनाना होगा। पूर्वी उ0प्र0 में संसाधनों की प्रचुरता है, गौरवशाली इतिहास होने के उपरान्त भी मात्र सोच (विजन) के अभाव में इसकी छवि पिछड़ेपन की बना दी गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओ0डी0ओ0पी0 के रूप में 75 जनपदों को जोड़ा है जो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का आधार है। इस पूर्वी क्षेत्र में प्रयागराज में कुम्भ का आयोजन, अयोध्या में दीपावली का उत्सव, सारनाथ, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, वाराणसी में 'देव दीपावली' तथा महत्वपूर्ण विकास कार्यों में पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे आदि उपलब्धियाँ हैं। कई जनपदों यथा– देवरिया, बलरामपुर, बस्ती, प्रतापगढ़ आदि में मेडिकल कालेज खुले हैं। हर जनपद में फोर लेन कनेक्टिविटी, ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फाईबर बिछाना, अयोध्या/सोनभद्र आदि कई जनपदों में एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। अतः प्रत्येक दिशा में अनेक विकास कार्य संचालित हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र हेतु गठित पूर्वान्चल विकास बोर्ड एक परामर्शी संस्था है, जिसके द्वारा संस्तुतियाँ प्रदान की जायेंगी।

- उद्घाटन सत्र के अन्त में मुख्य अतिथि/ विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिह्न दिया गया तथा दिनॉक 10 दिसम्बर, 2020 को राष्ट्रगान के साथ उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुआ।

प्राथमिक क्षेत्र

राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी

पूर्वांचल का सतत विकास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक पहल

मुद्दे, रणनीति एवम् भावी दिशा

10-12 दिसम्बर, 2020

कार्यक्रम स्थल

दीक्षा भवन
दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर-273009 (उ.प्र.)

आयोजक

नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

प्राथमिक क्षेत्र

पृष्ठभूमि

प्राथमिक क्षेत्र में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जिसमें कच्चे माल की निकासी और उत्पादन शामिल होता है, जैसे कि खेती, लॉगिंग, मछली पालन आदि। यह जनसांख्यिकीय रूप से व्यापक आर्थिक क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के समग्र सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधे से अधिक ग्रामीण परिवार इस क्षेत्र पर निर्भर करते हैं क्योंकि यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। राज्य के आर्थिक विकास में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और वानिकी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के विकास और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से स्पष्ट है कि उद्योगों के विकास के लिए एक व्यापक गुंजाइश है और भविष्य में यह निश्चित रूप से राज्य के बेरोजगार/भूमिहीन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यह हमारे समाज के जीवन स्तर में सुधार और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम के लिए भी सहायक होगा।

कृषि

- भारत में सबसे बड़ा आजीविका प्रदाता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- जी0डी0पी0 के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा योगदान देता है।
- समग्र ग्रामीण विकास के लिए स्थायी कृषि आवश्यक है।

मछली पालन

- इसमें विभिन्न प्रकार के अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन के सतत दोहन की व्यापक संभावनाएं हैं।
- वर्तमान में कैप्चरिंग फिशरीज, सेमी–इंटेंसिव एक्वाकल्चर और अनुभवजन्य खेती से लेकर पालन आधारित कैप्चर फिशरीज, गहन एक्वाकल्चर और ज्ञान–आधारित खेती पर जोर दिया जा रहा है।

पशुपालन

- पशुधन उत्पादों के माध्यम से आय सृजन, मसौदा शक्ति, सामाजिक–आर्थिक उत्थान, रोजगार के अवसर और मानव आबादी को बेहतर पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान।

वानिकी

- प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जंगल, झीलें, नदियॉ, वन्य जीवन आदि की भारतीय जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- देश की बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण पर दबाव बढ़ा रही है। इस प्रकार सरकार की प्राथमिक चिंता उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करना है।

रेशम के कीड़ों का पालन

- इसकी पहचान ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त होनहार उद्यमों में से एक के रूप में की गई है।
- आय और रोजगार के अवसरों के साथ–साथ कृषि–जैव विविधता के घटक के रूप में कृषि नियंत्रण और मिट्टी की उर्वरता में महत्वपूर्ण कृषि–वानिकी को शामिल करता है।

राष्ट्रीय वेबिनार में किये गये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी सत्रवार स्थिति निम्नवत् हैः–

तकनीकी सत्र–1

- श्री संजय भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा विभागीय की–नोट पेपर प्रस्तुत करते हुये विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।
- श्री प्रशान्त पी0 नन्दर्गिकार (फाउण्डर डायरेक्टर एण्ड इन्वेस्टर आफ पी0एस0ए0पी0) पुणे द्वारा गन्ना खेती में पी0एस0ए0पी0 के प्रयोग से किसानों की आय दोगुनी करने पर बल दिया गया।
- डा0 जे0सिंह, डायरेक्टर, यू0पी0सी0एस0आर0, शाहजहाँपुर द्वारा गन्ना खेती में उत्पादन लागत घटाने के विभिन्न तकनीकी पहलुओं को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही गन्ना खेती में इरिगेशन मैनेजमेन्ट, वाटर सेविंग इरीगेशन मैथड के बारे में प्रस्तुतीकरण किया गया।
- डा0 यू0पी0 सिंह, फार्मर डीन, फिशरीज, जी0बी0 पन्त यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नालॉजी, पन्तनगर द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने हेतु विस्तृत जानकारी दी गयी।
- सत्र के अन्त में श्री सुरेश राणा, मा0 मंत्री, गन्ना विकास विभाग द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र को चीनी के कटोरे के रूप में विकसित करने की प्रस्तावित योजना के बारे में बताया गया।

तकनीकी सत्र–2

- श्री सूर्य प्रताप शाही, मा0 मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा सहायतित "कृषि अवस्थापना सुविधा'' का पूर्वांचल क्षेत्र में अनुकूलतम उपयोग किये जाने विषयक सुझाव दिया।
- डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि एवं इससे जुड़ी श्रम शक्ति पर फोकस करने पर बल दिया।
- डा0 बिजेन्द्र सिंह, कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा हर्बल उत्पादों को अपनाये जाने, स्थानीय आवश्यकतानुसार सब्जी की खेती कराये जाने तथा बैंकों के माध्यम से कृषकों को आसानी से लोन दिलाने विषयक सुझाव प्रस्तुत किया गया।
- डा0 ए0के0 सिंह, उप महानिदेशक (उद्यान), आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली द्वारा महाराष्ट्र राज्य की तरह प्याज की खेती कराने तथा इसकी उन्नत प्रजाति का खरीफ मौसम में प्रयोग कर कृषकों की आय में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना दर्शायी गयी। इसके अतिरिक्त आम उत्पादन तथा नींबू की बागवानी पूर्वांचल क्षेत्र में किये जाने का सुझाव दिया गया।
- डा0 जगदीश सिंह, निदेशक, आई0सी0ए0आर0–आई0वी0ए0आर0, वाराणसी द्वारा वैश्विक मांग आधारित खेती पर बल देने, खाड़ी देशों में हरी मटर, मिर्ची के निर्यात के माध्यम से पूर्वांचल के कृषकों की आय में वृद्धि हेतु सुझाव दिया गया।

तकनीकी सत्र–3

- डा0 ए0पी0 राव, निदेशक प्रसार, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में मत्स्य आहार, बीज, उर्वरक, औषधि की कमी पर प्रकाश डालते हए इको टूरिज्म पर आधारित मत्स्य पालन पर बल दिया गया।
- डा0 एस.के. सिंह, निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा ''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'' के अन्तर्गत पूर्वांचल क्षेत्र के जनपदों की वित्तीय वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण करते हुए मत्स्य पालन में आ रही विविध समस्याओं यथा– तालाबों की खराब स्थिति, जल संसाधन का कम उपयोग आदि को दूर करने का सुझाव दिया गया।
- डा0 संजय कुमार श्रीवास्तव, निजी उद्यमी, महराजगंज द्वारा वियतनामी मूल की "पैंगिसयस'' मछली की विशेषता व उसके व्यवसाय से आय वृद्धि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मत्स्य बीज परिवहन को त्वरित किये जाने पर बल दिया गया।

तकनीकी सत्र–4

- श्री नरेन्द्र कुमार पटेल, निदेशक, राज्य रेशम बोर्ड द्वारा रेशम पालन हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा– कीट पालन, गृह उपकरण, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि की

स्थिति प्रस्तुत की गयी। इसके साथ ही शहतूत व अर्जुन वृक्षारोपण पर जोर दिया गया तथा "सिल्क ग्राम" का चयन कर कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाना बताया गया।

- श्री ए0पी0 श्रीवास्तव, निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा पूर्वांचल के 11 जनपदों में आई0आई0ए0आर0 के सहयोग से "काला नमक चावल'' योजना से आच्छादित कर निर्यात प्रोत्साहन पर बल दिया गया। पूर्वान्चल में 3000 सोलर पम्प प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन से अवगत कराया।
- श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, मा0 मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा आधारभूत सुविधाओं से सम्बन्धित चल रही योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सभी विभागों को एकीकृत रूप में काम करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक/गुणात्मक परिवर्तन किये जाने पर बल दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र–5</u>

- श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा पूर्वान्चल में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के बारे में बताया गया। कृषकों को वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण पर बल दिया गया। गुजरात पैटर्न पर दुग्ध उद्योग का विकास किये जाने की प्रक्रिया को अपनाने पर भी बल दिया गया।
- प्रोफेसर राकेश सिंह, विभागाध्यक्ष, फूड साइन्स एण्ड टेक्नालॉजी, यूनिवर्सिटी आफ जार्जिया द्वारा खाद्य एवं सुरक्षा में उत्पन्न चुनौतियां एवं उनके निस्तारण पर फोकस करते हुए खाद्य सामग्रियों के पैकेजिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं इनोवेशन पर चर्चा की गयी।
- डा0 आर0के0सिंह, निदेशक, आई0वी0आर0आई0, बरेली द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार की सम्भावना के बारे में चर्चा करते हुए पशुधन के क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों विशेषकर गर्भाधान की समस्या, अवस्थापना सुविधाओं के अभाव पर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूर्वान्चल के जनपदों के आच्छादन के बारे में भी अवगत कराया गया।
- श्री विवेक पठानिया, नाबार्ड, लखनऊ द्वारा दुग्ध फार्मिंग की विशेषता बताते हुए इसे कृषकों की आय में वृद्धि का साधन बताया गया। इसके साथ ही लोकल मार्केटिंग को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- डा0 बी0पी0मिश्रा, आई0सी0ए0आर0–आई0वी0आर0आई0, इज्जतनगर, बरेली द्वारा भारत में "पशुधन उत्पादन" योजना पर प्रस्तुतीकरण करते हुए स्वदेशी पशुधन की चुनौतियों एवं समस्या तथा उसके निराकरण पर चर्चा की गयी। चर्चा में दुग्ध उद्योग की क्षमता को बढ़ाने व उससे मिलने वाले रोजगार को बढ़ाने पर बल दिया गया।

- श्री सरोज के0 स्वीन, आई0सी0ए0आर0–सी0आई0एफ0ए0, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा सजावटी मछली व्यवसाय से होने वाले लाभ व आय के स्रोत को बढ़ाने, वैश्विक एवं भारतीय परिपेक्ष्य में सजावटी मछली की प्रगति तथा प्रजाति का विस्तार करने पर जोर दिया गया।

तकनीकी सत्र–6

- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, आई0आई0पी0आर0, कानपुर द्वारा तिलहन फसलों की उन्नतशील प्रजातियों पर प्रस्तुतीकरण करते हुए कदन्त में मौजूद पोषक तत्वों से आधुनिक बीमारियों से निजात पाने में मदद मिलने के साथ ही कदन्त बेकरी उत्पाद प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया।
- डा0 अरविन्द कुमार, निदेशक, इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इस्टीट्यूट, वाराणसी द्वारा पारम्परिक उच्च गुणवत्ता के चावल को प्रीमियम इनकम जनरेंटिंग राइस में परिवर्तित करके आय में बढ़ोत्तरी करने, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने तथा चावल आधारित कृषि खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु उससे सम्बंधित खेती को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया।
- श्री अजय कुमार बोहरा, बोहरा आर्गेनिक फार्म, हरियाणा द्वारा कार्बनिक खेती के विभिन्न पहलुओं यथा–प्रशिक्षण, विपणन, उत्पादन का प्रस्तुतीकरण करते हुए पेस्टीसाइड के प्रयोग से खेती में मृतप्राय सूक्ष्म जीवों को घरेलू वेस्ट मैटेरियल का उपयोग करके पुनः प्राकृतिक खेती में वापस लाने पर जोर दिया गया।
- डा0 संजय कुमार, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सीड रिसर्च, मऊ द्वारा कृषकों के लिए बीज सम्बंधी किये जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए पूर्वान्चल क्षेत्र में कृषि विकास के लिए उन्नत बीज उत्पादन क्षमता में 40–60 प्रतिशत की वृद्धि संस्थान द्वारा किये जाने से अवगत कराया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा "सही बीज–सही समय–सही जगह" मूलमंत्र अपनाने पर बल दिया गया।

तकनीकी सत्र–7

- श्री शंकर ए0 पाण्डेय, सी0जी0एम0, नाबार्ड, लखनऊ द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारकों यथा–क्रेडिट इन्टेन्सिटी का कम होना, 11 जनपदों में ऋण–जमा अनुपात कम होना तथा सहकारी समितियों के कमजोर होने विषयक तथ्य चिन्हित किये गये। इसके साथ ही स्थानीय संसाधनों को चिन्हित कर वैश्विक लक्ष्य व सोच के साथ आगे बढ़ने, एफ0पी0ओ0 को मजबूत करने, पैक्स को नई सोच, तकनीकी एवं पारदर्शिता के साथ सुदृढ़ करते हुए कप्यूटराइजेशन कर बहुआयामी बनाने पर जोर दिया गया।
- डा0 आर0के0 मित्तल, कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा आर्गेनिक खेती की सहायता से पूर्वान्चल को उत्पादन, विपणन

तथा निर्यात सेक्टर में "हब" बनाने पर बल दिया गया। इसके साथ ही प्लांट न्यूट्रिशन हेतु कृषकों की पहचान कर तकनीक आधारित प्रशिक्षण दिये जाने पर भी बल दिया गया।

- डा0 प्रबोध कुमार त्रिवेदी, निदेशक, सीमैप द्वारा पूर्वान्चल में "खुशबूदार फसलों (ऐरोमेटिक क्राप्स)" की खेती पर कृषकों की आय में वृद्धि पर प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा गोरखपुर में प्रस्तावित "मानव गार्डेन" जिसके द्वारा कौन सा प्लांट मनुष्य के किस अंग के लिए आवश्यक है, पर चर्चा की गयी।
- श्री उमाशंकर सिंह, निदेशक, इण्टरनेशनल पोटैटो सेन्टर ऑफ साउथ एशिया द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में आलू उत्पादन पर प्रस्तुतीकरण करते हुए उसमें आने वाली समस्याओं, निदान तथा उसके व्यवसायीकरण पर चर्चा की गयी। इसके साथ ही आलू की उन्नत प्रजातियों के बारे में अवगत कराते हुए आलू कृषकों द्वारा उत्पादित आलू के उन्नत बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया।
- डा0 संदीप कुमार, सतना द्वारा भारतीय दुग्ध सेक्टर पर चर्चा करते हुए उसके माध्यम से पूर्वान्चल क्षेत्र में दुग्ध उत्पादों का सुदृढ़ विपणन कर कृषकों की आय में वृद्धि पर बल दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र–8</u>

- श्री दारा सिंह चौहान, मा0 मंत्री, वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान विभाग द्वारा अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में वन सम्पदा के माध्यम से "प्रति व्यक्ति आय" बढ़ाने के साथ ही वन आच्छादन तथा इको–टूरिज्म को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया।
- श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में इको–पर्यटन को बढ़ावा देने से सम्बंधित योजनाओं के बारे में बताया गया। वनटांगिया से सम्बंधित ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर अन्य नागरिकों के समान सुविधाएं देने के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही प्राथमिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने/उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
- श्री भीमसेन, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र के जनपदों में वनाच्छादन का विवरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय वन नीति के मानक के अनुसार वनाच्छादन को 33 प्रतिशत करने हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों यथा–निःशुल्क पौध वितरण, नमामि गंगे परियोजना द्वारा पूर्वान्चल के जनपदों में प्रगति की स्थिति बतायी गयी। इसके अतिरिक्त पूर्वान्चल के 9 जनपदों में "राष्ट्रीय बांस मिशन परियोजना" का संचालन व इसके उत्पाद से कृषकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आय में वृद्धि होने से अवगत कराया गया।

- श्री अमित पाण्डेय, साइंटिस्ट, एफ0आर0आई0, देहरादून द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से शाल/साखू पौधों के विकास के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित किया गया। इसमें लगने वाले कीड़ों से इसकी क्षति रोकने के उपायों का प्रस्तुतीकरण किया गया। तदोपरान्त इसे संरक्षित करने पर बल दिया गया।
- श्री बी0एन0 सिंह, सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट, गोरखपुर द्वारा बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पौधों की प्रजाति पर फोकस करने तथा सी0आर0डी0 फार्म गोरखपुर द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे सुविधाओं के बारे में अवगत कराया गया। "एकीकृत फसल प्रबन्धन" रूद्रपुर, देवरिया का प्रयोगात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षत्रों में धान की बीजों की प्रजातियों पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करते हुये कृषकों को होने वाले लाभ से अवगत कराया।
- श्री संजय मल्ल, प्रभागीय निदेशक, वन विभाग, गोरखपुर द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में वन सम्पदा और इस पर आधारित परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। वन सम्पदा का स्कोप यथा– कागज उद्योग, कच्चे माल के रूप में लकड़ी आधारित उत्पाद, जो कृषकों को रोजगार व लाभ में प्रगतिशील कदम हो सकता है, के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा ''ग्राम स्तरीय समिति'' के माध्यम से कृषकों को बॉस उत्पादों से रोजगार व लाभ के बारे में चर्चा की गयी।

<u>तकनीकी सत्र–9</u>

- डा0 पंजाब सिंह, पूर्व महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0 द्वारा कृषि विविधता इन्फ्रास्ट्रक्चर में एफ0पी0ओ0 की व्यवस्था, कृषि मार्केटिंग को विकसित करने हेतु तकनीकी सुधार, किसानों को प्रशिक्षित करने तथा नीतिगत सुधार करके लाभकारी बनाने पर बल दिया गया।
- श्री भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव, पशुपालन द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र में पशु उत्पादन कम होने के कारण इसको प्रोत्साहन देकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही उनके द्वारा टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा पर भी बल दिया गया।
- डा0 ओमकार सिंह, कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रॉची द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने, क्राप उत्पादन घनत्व एवं क्षमता वृद्धि का उपयोग करके सुधार करने, व्यवसायीकरण हेतु आर0 एण्ड डी0 पॉलिसी संरचना तथा पी0एम0के0एस0वाई0 फ्लैगशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
- श्री अविनाश चन्द्रा, निदेशक, पशुपालन, उ0प्र0 द्वारा कामर्शियल लेयर की इकाई बढ़ाने, 50 की जगह 100 चूजे उपलब्ध कराने, पशुओं का बीमा कराने तथा चारे की समस्या दूर करने हेतु चारागाह के क्षेत्र को बढ़ाने पर बल दिया गया।

- डा0 डी0आर0 कन्नौजिया, सी0आई0एफ0ए0, भुवनेश्वर द्वारा हैचरी के लिये समुद्र के पानी को लाभदायक बनाने पर बल दिया गया।

राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी

पूर्वांचल का सतत विकास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक पहल

मुद्दे, रणनीति एवम् भावी दिशा

10-12 दिसम्बर, 2020

विनिर्माण क्षेत्र

कार्यक्रम स्थल : संवाद भवन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर-273009 (उ.प्र.)

आयोजक

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विनिर्माण क्षेत्र

पृष्ठभूमि

पूर्वान्चल उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित और श्रम प्रचुर क्षेत्र है। यह क्षेत्र औद्योगिक विकास के संदर्भ में कम विकसित है। इस क्षेत्र में सामाजिक न्याय के साथ रोजगार, क्षेत्रीय संतुलन और सतत विकास की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र पूँजी संचय के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। पूँजी संचय विकास के कुल स्रोतों में से एक है। विनिर्माण क्षेत्र ने परम्परागत रूप से आर्थिक संवृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन (MSME) का योगदान कुछ अवसंरचनात्मक चुनौतियों, क्षेत्रीय असमानताओं से युक्त होने के बावजूद समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में काफी अभूतपूर्व रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन (MSME) बेहतर विकास दर को बनाए रखने और रोजगार के अवसर पैदा करने में पूर्वान्चल की रीढ़ है। इस सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन (MSME) सेक्टर पूर्वान्चल विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः पूर्वान्चल से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करना और विनिर्माण क्षेत्र के निम्नलिखित उप–विषयों से सम्बन्धित मुद्दों और रणनीतियों की पहचान करना आवश्यक है।

वेबिनार/संगोष्ठी के लिए उप–विषय

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन (MSME)
- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
- खादी एवं ग्रामोद्योग
- लोक निर्माण
- ग्रामीण अभियन्त्रण
- ऊर्जा
- अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
- नगर विकास
- आवास एवं शहरी नियोजन
- पंचायती राज
- पर्यावरण
- भूतत्व एवं खनिकर्म
- राजस्व, अभाव एवं दैवी आपदा राहत

राष्ट्रीय वेबिनार में किये गये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी सत्रवार स्थिति निम्नवत् हैः–

<u>तकनीकी सत्र–1</u>

- श्री आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने विभागीय की–नोट पेपर प्रस्तुत करते हुये "Industrial Investment and Employment Policy", "Proactive Governance Reforms and Post Covid -19 New Policy", "Ease of Doing Business, Industrial Park/Region" के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
- प्रो0 ए0पी0 पाण्डेय, पूर्व वी0सी0, मणिपुर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदेश के एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के अन्तर्गत हैण्डलूम उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु हैण्डलूम उद्योग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया।
- प्रो0 एन0एम0पी0 वर्मा, पूर्व वी0सी0, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :–
  - मत्स्य पालन, दुग्ध पदार्थों के उत्पादन तथा निर्यात को प्रोत्साहन।
  - पूर्वी क्षेत्र के वाटर प्रोन एरिया (Water Prone Area) होने से मिनरल वाटर प्लान्ट की स्थापना।
  - कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की ईकाइयों की स्थापना।
  - सिंचाई प्रणाली में सुधार।

- प्रो0 राजेश कुमार पाल, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, एम0जी0के0वी0पी0, वाराणसी द्वारा पूर्वी क्षेत्र के अति पिछड़े जनपदों यथा– अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मिर्जापुर के उत्पादों को प्रोत्साहन तथा निर्यात में बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया गया। साथ ही पूर्वान्चल क्षेत्र के जलवायु, पर्यावरण, जनमानस तथा स्किल के अनुसार योजनायें बनाये जाने का सुझाव दिया गया।
- डा0 गौरव कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक, उ0प्र0 सेन्सस द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में बायो, मेडिकल एवं कंस्ट्रक्शन वेस्ट के उपयोग हेतु वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेन्ट पर बल दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र–2</u>

- श्री चौधरी उदयभान सिंह, मा0 राज्यमंत्री, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में एम0एस0एम0ई0 के योगदान एवं रूपरेखा की जानकारी दी गयी तथा अवगत कराया गया कि एम0एस0एम0ई के अंतर्गत ''वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'' लागू होने से अच्छे परिणाम आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में कुटीर

उद्योगों और हस्तशिल्प की बेहद समृद्ध परंपरा है। मा0 मुख्यमंत्री जी लगातार ओ0डी0ओ0पी0 को अधिकतम रोजगार के लिए एक मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

- श्री नवनीत कुमार सहगल, अपर मुख्य सचिव, एम0एस0एम0ई0 द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में इस सेक्टर के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किये जाने पर बल दिया गया।
- डा0 उमेश प्रताप सिंह, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फल एवं सब्जियों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को एम0एस0एम0ई0 के अंतर्गत स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया, जिससे क्षेत्र में रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी।
- श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष, गैलेण्ट ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, गोरखपुर द्वारा क्षेत्र में रोजगार दूर करने हेतु एग्रोबेस इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया गया। उन्होने यह भी अवगत कराया कि एग्रोबेस वेस्ट प्रोडक्ट हेतु बेस्ट मेनेजमेन्ट तकनीक का उपयोग करना चाहिए जो कि पावर जनरेशन एवं खाद बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी।
- प्रो0 मनोज कुमार अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र एवं निदेशक डॉ शंकर दयाल शर्मा इस्टीट्यूट आफ डेमोक्रेसी, लखनऊ द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड, पावर आदि निर्माण कार्यों का सुझाव दिया गया।

<u>**तकनीकी सत्र–3**</u>

- आयुक्त/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" के अंतर्गत किये जा रहे उत्पादों यथा–हैण्डलूम, कारपेट, हैण्डीक्राफ्ट, हार्डवेयर इत्यादि को ई–कामर्स से जोड़ा जा रहा है। पूर्वान्चल क्षेत्रों में इन उत्पादों की पैकेजिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी मेन्टेन करने हेतु कामन फैसेलिटीज सेन्टर स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- प्रो0 शक्ति कुमार, चेयरमैन, सेन्टर फार इकोनोमिक स्टडीज एण्ड प्लानिंग, जे0एन0यू0, दिल्ली द्वारा माइक्रो एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया गया ताकि पूर्वान्चल क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार सृजन हो सके।
- प्रो0 जे0बी0 कोमराया, डिपार्टमेन्ट आफ इकोनामिक्स, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में माइक्रो एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के अंतर्गत विकसित किये जाने एवं निर्यात को बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया, जिससे क्षेत्र में रोजगार सृजन हो सके।
- प्रो0 सी0के0पी0शाही, बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा सुझाव दिया गया कि एम0एस0एम0ई0 को पृथक रूप से न देखते हुये समग्र सेक्टर के विकास की दृष्टि से एकीकृत नीति बनायी जानी चाहिए।

तकनीकी सत्र–4

- डा0 तनवीर आलम, निदेशक, इण्डियन इस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, भारत सरकार द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के अंतर्गत हो रहे उत्पादों की मार्केटिंग, पैकेजिंग, वेयर हाऊस की स्थापना का सुझाव दिया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 20.25 प्रतिशत मांस का भी उत्पादन करता है और भारत में सबसे अच्छी जगह रखता है लेकिन केवल 2.19 प्रतिशत अंडे उत्पादित करता है। उन्होंने कहा कि उच्च दूध उत्पादन के बावजूद, केवल 44 प्रतिशत लोगों के लिए ही प्रतिदिन दूध उपलब्ध हो पाता है। मुख्य मुद्दे गायों और भैंसों का बांझपन, हरे चारे की अपर्याप्त उपलब्धता, कम टीकाकरण दर, कौशल और उद्यमशीलता की कमी है।
- डा0 शैलेन्द्र सिंह, निदेशक, आई0आई0एम0, रांची द्वारा उद्योगों एवं संगठनों में प्रबन्धन की कार्यशैली की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गयी।
- श्री वीरेन्द्र प्रसाद, प्रधानाचार्य, रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर, खादी ग्रामोद्योग, गोरखपुर ने विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
- श्री सुनील कुमार, संयुक्त आयुक्त, ओ0डी0ओ0पी0, लखनऊ द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 के अंतर्गत किये जा रहे उत्पादों की सही पैकेजिंग, मार्केटिंग एवं एक्सपोर्ट की व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने का सुझाव दिया गया।

तकनीकी सत्र–5

- श्री श्रीकान्त शर्मा, मा0 मंत्री, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र के सतत विकास के बिना उत्तर प्रदेश का विकास अधूरा है। पूर्वान्चल के सतत विकास हेतु इस क्षेत्र में निर्बाध 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है।
- श्री अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एवं उपभोग से सम्बंधित जानकारी प्रदान की गयी तथा क्षेत्र के विकास हेतु की–इश्यू, क्रिटिकल स्ट्रैटजी एवं एक्शन प्लान से भी अवगत कराया गया।
- प्रो0 पी0के0 घोष, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अतिरिक्त सोलर ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक है।
- प्रो0 गोविन्द पाण्डेय, डीन डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किये जाने एवं सालिड वेस्ड मेनेजमेंट, एफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने का सुझाव दिया गया,

जिससे कि क्षेत्र की नदियां एवं तालाब दूषित न हों। पूर्वान्चल क्षेत्र में एअर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन भी स्थापित किये जाने पर जोर दिया गया।

- श्री सरोज कुमार, प्रबंध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में की जा रही विद्युत आपूर्ति एवं आनलाइन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया गया।

तकनीकी सत्र–6

- श्री विजय कश्यप, माननीय राज्यमंत्री, राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण, उ0प्र0सरकार द्वारा राजस्व विभाग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गयी ।
- श्री आर0पी0शाही, ले0 जनरल (सेवानिवृत्त)/उपाध्यक्ष, यू0पी0 स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, लखनऊ द्वारा नेशनल डिजास्टर पालिसी एवं स्टेट डिजास्टर पालिसी की जानकारी प्रदान करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट से सम्बन्धित सुझाव दिये गये।
- सुश्री मनीषा त्रिघाटिया, आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में भूमि अभिलेखों का रख–रखाव डिजिटलाइजेशन, ई–गवर्नेन्स, भूमि क्रय एवं पट्टा से सम्बंधित नियमों एवं नियमावली की जानकारी प्रदान की गयी। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल के 12 जनपदों में वर्तमान फसली के अन्तर्गत खतौनी का पुनरीक्षण तथा अंश निर्धारण का कार्य प्रगति पर है।
- प्रो0 ध्रुव सेन सिंह, डिपार्टमेन्ट आफ जियोलाजी एवं निदेशक, यू0जी0सी0–एच0आर0 डी0सी0, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।
- प्रो0 नरेन्द्र कुमार राना, डिपार्टमेन्ट आफ जियोग्राफी, डी0डी0यू0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण से सम्बंधित बिन्दुओं को रेखांकित किया तथा बाढ़ आपदा, नदी स्थानान्तरण के फलस्वरूप अस्तित्व में आये छोटी– बड़ी नदियां एवं तालाब में सम्भावित आजीविका संवर्धन पर प्रकाश डाला।

तकनीकी सत्र–7

- श्री केशव प्रसाद मौर्य, मा0 उप मुख्यमंत्री एवं मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में रोड नेटवर्क एवं अन्य विकास कार्यों की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल के जनपदों में सड़कों में अत्यधिक सुधार हुआ है। ग्रामीण मार्गों का स्तर ऊँचा कर स्टेट हाईवे बनाया गया है। पूर्वान्चल के सभी जनपदों को राज्य मार्ग से जोड़ा गया है। पूर्वान्चल क्षेत्र में कई मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा रही है। इस क्षेत्र में काफी विकास कार्य होने के कारण यहाँ की जनता लाभान्वित हो रही है तथा उन्हें रोजगार भी मिल रहा है।

- श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में रोड नेटवर्क तथा सेतुओं की जानकारी प्रदान करते हुए पूर्वान्चल के विभिन्न जनपदों में संचालित एवं निर्माणाधीन रोड, रेल सेतु, नदी सेतु तथा लघु सेतु का विवरण प्रस्तुत किया गया।
- प्रो0 जे0 पी0 पाण्डेय, कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में सौर ऊर्जा के महत्व की जानकारी देते हुए सुझाव दिया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र के सभी सेक्टरों यथा—कृषि, उद्योग आदि में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिये।
- श्री एम0पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा सुगम यातायात हेतु गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण को आवश्यक बताते हुए पूर्वान्चल में रोड नेटवर्क का निर्माण और अनुरक्षण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने से अवगत कराया गया। इसके साथ ही पूर्वान्चल के जनपदों में नवीन मार्गों, पुराने मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, पुलिया एवं सेतुओं के निर्माण का विवरण प्रस्तुत करते हुए भवनों का निर्माण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया।
- प्रो0 श्रीराम चौरसिया, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र में विकास के कार्य काफी हुए हैं किन्तु इनके सुदृढ़ीकरण की अभी भी आवश्यकता है। पूर्वान्चल में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए रोड नेटवर्क का निर्माण किया जाय। राजस्व ग्रामों में दोहरी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। लोक निर्माण विभाग को छोड़कर सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्य निर्माण एजेन्सियों द्वारा लोक निर्माण के मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण कार्य कराये जाने की व्यवस्था/नीति बनाने का भी सुझाव दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र—8</u>

- श्री आशुतोष टंडन, मा0 मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु नगर विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाए संचालित की जा रही हैं। पूर्वान्चल क्षेत्र में शहरीकरण हेतु अत्यधिक कार्य किया जा रहा है। साथ ही नागरिक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र की प्रास्थिति प्रस्तुत करते हुए नगरीय क्षेत्र में मानकों के अनुसार पेयजल की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सीवरेज, जल भराव तथा उच्च स्तरीय पर्यावरण कार्य, नदियों को प्रदूषण मुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा नगर विकास को

आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न स्रोत विकसित करने से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी।

- प्रो0 संजय मेधावी, डिपार्टमेन्ट आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड के कारण पूर्वान्चल क्षेत्र में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। यहां के लोगों में पर्याप्त स्किल नहीं है। अतः उन्हें पूर्वान्चल के जनपदों में छोटे एवं मध्यम उद्यम लगाते हुए रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से उद्योग लगाये जाने से पूर्व, सरकार द्वारा युवाओं को विशेष स्किल तकनीकी संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही उनके उत्पादों की मार्केटिंग निर्यात तथा कन्सल्टेन्सी के क्षेत्र में भी सहयोग/प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता बताई गयी।
- श्री फैरोजन एवं सुश्री दीपिका कुमारी द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र विशेषकर गोरखपुर में टेराकोटा प्रोडक्ट से सम्बन्धित इण्डस्ट्रीज की जानकारी प्रदान करते हुए टेराकोटा प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, विधि, मार्केटिंग, निर्यात आदि की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इनको बनाने हेतु कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है तथा यह लो–कास्ट इन्वेस्टमेन्ट है। इसको ओ0डी0ओ0पी0 के तहत प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

<u>तकनीकी सत्र–9</u>

- श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि विनिर्माण क्षेत्र में पूर्वान्चल के जनपदों में एम0एस0एम0ई0 का विशेष योगदान है। इस क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत भागीदारी एम0एस0एम0ई0 विभाग की है। क्षेत्र में एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत उद्यम स्थापित किये जाने हेतु शिक्षित व कुशल व्यक्तियों को आधुनिक तकनीक, संसाधन व अन्य समुचित आवश्यकताओं/व्यवस्थाओं पर ध्यान दिये जाने का सुझाव दिया गया।
- प्रो0 आलोक राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल एवं अन्य संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु उचित प्रबन्धन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि क्षेत्रीय लोगों को इसका लाभ हो सके।
- प्रो0 सतीश कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था को देखते हुए इसमें सुधार एवं अन्य अधिकार दिये जाने का सुझाव दिया गया।
- डा0 मनीष कुमार पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिये जाने

तथा इसका उपयोग कृषि व छोटे–छोटे उद्यमों तथा अन्य भवनों में किये जाने का सुझाव दिया गया।

- श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों का वर्णन किया गया।

राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी

पूर्वांचल का सतत विकास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक पहल

मुद्दे, रणनीति एवम् भावी दिशा

10-12 दिसम्बर, 2020

सेवा क्षेत्र

कार्यक्रम स्थल : रसायन विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ.प्र.)

आयोजक

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सेवा क्षेत्र

पृष्ठभूमि

समकालीन परिदृश्य में भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सेवा क्षेत्र आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के अन्तर्गत सर्वाधिक गतिशील एवं जीवन्त क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह बाजार एकीकरण और वैश्वीकरण में एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। सेवा क्षेत्र रोजगार सृजन, मूल्यसंवर्धन एवं आय सेवाओं के बढ़ते हुये उत्कृष्ट प्रदर्शन से सम्बन्धित है। सेवा क्षेत्र ने न केवल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदान दिया है, बल्कि इसने उल्लेखनीय रूप से विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया है तथा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हुये वृहद पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। भारत के सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त, रियल स्टेट, व्यावसायिक सेवायें, आतिथ्य, पर्यटन एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है।

पूर्वान्चल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के वृहद क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र स्वतंत्रता के उपरान्त नवोन्मेषी विचारों की कमी के कारण विकास से वंचित रहा है। पूर्वान्चल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है किन्तु सेवा क्षेत्र के विकास एवं विस्तार से आर्थिक विकास की गति को और तीव्र कर राष्ट्रीय स्तर के विकास प्रारूप के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस परिक्षेत्र में सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित अनेक मुद्दे एवं चुनौतियॉ यथा–सूचना प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त विकास, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास की उपेक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु सुविधाओं की कमी, परिवहन सुविधाओं का अभाव, वित्तीय सहायता एवं समावेशन की अप्राप्यता एवं ढांचागत उपलब्धता की अकुशलता इत्यादि है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ सेवा क्षेत्र के इन सभी मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रख्यात विशेषज्ञों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं एवं उत्कृष्ट शिक्षाविदों के द्वारा सार्थक बहस एवं समाधान हेतु इस वेबिनार का आयोजन किया गया, जिससे अन्य क्षेत्रों के साथ ही सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ एवं विस्तारित करते हुए पूर्वान्चल के आर्थिक विकास की समस्याओं का निवारण किया जा सके। इस मेगा वेबिनार के माध्यम से उभरकर आये निष्कर्ष सरकार को नीति निर्माण करने के साथ ही साथ पूर्वान्चल के समग्र विकास में सहायक होंगे।

राष्ट्रीय वेबिनार में किये गये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी सत्रवार स्थिति निम्नवत् हैः–

तकनीकी सत्र–1

- प्रो0 एम0एम0 त्रिपाठी, ई0सी0ई0 विभाग, तकनीकी विश्वविद्यालय, दिल्ली ने बताया कि पूर्वान्चल सहित उत्तर प्रदेश में वर्तमान रोजगार की स्थिति मुख्य रुप से कृषि क्षेत्र, खनन

क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में है। भविष्य में कौशल विकास हेतु आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, इन्टरनेट आफ थिंग्स, ब्लाक चेन, साईबर सिक्योरिटी, 5जी कम्युनिकेशन जैसे बदलाव लाने चाहिये।

- श्री आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने की–नोट पेपर में विभागीय उपलब्धियाँ दर्शाते हुये इस सेक्टर में भावी विभागीय योजनाओं का रोड मैप प्रस्तुत किया।
- प्रो0 वी0एस0 त्रिपाठी, एम0एल0एन0आई0टी0, प्रयागराज ने पूर्वान्चल में इस क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमियों से उबरने के लिये केन्द्र सरकार की पहल की आवश्यकता पर बल दिया।
- डा0 शिप्रा सुमन, सेन्टर ऑफ मेडिकल इमेजिंग, यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ लंदन ने पूर्वान्चल में महिलाओं के विकास हेतु उन्हें तकनीकी शिक्षा दिलाये जाने पर बल दिया।
- प्रो0 क्षितिज अवस्थी, आई0आई0एम0, लखनऊ ने शिक्षा के निम्न स्तर, खराब कौशल प्रशिक्षण के कारण श्रम बल की समस्याओं, इससे संबंधित रोजगार पर प्रस्तुतीकरण किया।
- सत्र के सह–अध्यक्ष प्रो0 एस0एन0 तिवारी द्वारा पूर्वान्चल के गन्ने का केन्द्र होने के कारण गन्ने की पैदावार बढ़ाने में केन्द्र एवं राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की गयी।

<u>तकनीकी सत्र–2</u>

- डा0 संतोष कुमार विश्वकर्मा, आई0आई0टी0, इन्दौर द्वारा स्टार्टअप एवं इनोवेशन के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया गया तथा पूर्वान्चल में छोटी इन्डस्ट्रीज होने के कारण टीम बनाकर छोटी इन्डस्ट्रीज में जाने तथा अपना इनोवेशन अप्लाई करने का सुझाव दिया गया।
- प्रो0 एस0पी0 त्रिपाठी, डिपार्टमेन्ट ऑफ कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, आई0ई0टी0, लखनऊ द्वारा पूर्वान्चल के टूरिस्ट स्थानों यथा काशी, गोरखपुर, कुशीनगर तथा अयोध्या आदि के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया गया तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट हेतु रोड, रेलवे, विद्युतीकरण, इन्टरनेट सुविधा तथा डाटा सेन्टर स्थापित करने का सुझाव दिया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्वान्चल में महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी/इन्स्टीट्यूट यथा– बी0एच0यू0,गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी प्रयागराज, एम्स गोरखपुर तथा अन्य मेडिकल संस्थान हैं। इनसे निकली प्रतिभाओं का उपयोग अन्य प्रदेशों तथा देशों में हो रहा है परन्तु पूर्वान्चल क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है।

- श्री फ्रैंक इस्लाम, अध्यक्ष एवं सी0ई0ओ0, इनवेस्टमेन्ट ग्रुप अमेरिका (मूलतः आजमगढ़ निवासी) द्वारा पूर्वान्चल में निवेश की अनेक सम्भावनाओं से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कृषि निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- प्रो0 डी0के0 द्विवेदी, डीन एकेडमिक्स, एम0एम0 यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास के लिये सोलर एनर्जी पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास में सोलर एनर्जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

तकनीकी सत्र–3

- प्रो0 के0एन0 सिंह, कुलपति, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने अपने व्याख्यान में पर्यटन के माध्यम से रोजगार दिये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें बिहार से बोध गया, वैशाली, वाराणसी तथा कुशीनगर से लेकर नेपाल तक टूरिज्म का स्कोप होने से अवगत कराया तथा इन क्षेत्रों में परिवहन सुविधायें बढ़ाने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण तथा कुशीनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण एवं बुलेट ट्रेन प्रस्तावित होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
- श्री शिवपाल सिंह, विशेष सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन ने पूर्वान्चल में पर्यटन के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजनाओं तथा कार्यों के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया।
- प्रो0 मनोज दीक्षित, पूर्व कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने पूर्वान्चल में निजी क्षेत्र के सहयोग से धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को बेहतर यातायात सुविधा देकर विकसित करने पर बल दिया।
- प्रो0 राणा पी0वी0 सिंह, अध्यक्ष, एशियन कल्चर लैण्ड स्पेस एसोसिएशन एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल, बी0एच0यू0, वाराणसी ने पूर्वान्चल के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन की सम्भावनाओं के विषय पर अपना प्रस्तुतीकरण किया तथा अवगत कराया कि अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी को मिलाकर ''गोल्डेन ट्राईऐंगिल स्पीरिचुअल'' टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- डा0 प्रवीण राणा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी ने अपने व्याख्यान में कहा कि पूर्वान्चल में राष्ट्रीय धरोहरों के साथ पंचकोसी यात्रा, सलखन फासिल पार्क (सोनभद्र) तथा प्रागैतिहासिक शैल चित्र, लखनिया पेंन्टिग आदि के संरक्षण की आवश्यकता है।

तकनीकी सत्र–4

- श्री एस0पी0 तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, आई0आई0टी0 जोधपुर द्वारा ग्रीन इलेक्ट्रानिक्स फॉर सस्टनेबुल डेवलेपमेन्ट के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया गया।
- सुश्री विपुल वार्ष्णेय, आर्किटेक्ट, आथर एण्ड अर्बन प्लानर, लखनऊ द्वारा बुद्धिष्ट सर्किट का विकास कर इन्टरनेशनल टूरिज्म पर बल देते हुए बताया गया कि जापान, म्यांमार, थाईलैण्ड, श्रीलंका आदि देशों से आने वाले टूरिस्टों के भारत आने से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्राप्त होने के दृष्टिगत इन टूरिस्टों पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इस हेतु इन्हें पर्याप्त सुरक्षा तथा अच्छी सड़कें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- डा0 मनीष मिश्रा, लीड कन्सलटेन्ट, नेशनल स्किल डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा पूर्वान्चल के विकास हेतु स्किल डेवलपमेन्ट बढ़ाये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।

तकनीकी सत्र–5

- प्रो0 मुरली मनोहर पाठक, संस्कृत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने पूर्वान्चल की संस्कृति विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि हमारे संस्कार, हमारी परम्परा ही हमारी संस्कृति है जिसका संरक्षण और प्रसार बहुत ही आवश्यक है।
- प्रो0 प्रत्यूष दूबे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने भारतीय संस्कृति की व्याख्या करते हुए इसे विश्व की अनूठी और प्राचीन संस्कृति बताया।
- डा0 अखिल मिश्रा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल का विकास सांस्कृतिक विकास के साथ हुआ है, इसके साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि पूर्वान्चल की संस्कृति कृषि पर आधारित है। अतः कृषि के विकास की आवश्यकता है।
- प्रो0 अरविन्द त्रिपाठी, हिन्दी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने अपना व्याख्यान पूर्वान्चल की सांस्कृतिक विरासत विषय पर दिया और कहा कि पूर्वान्चल की संस्कृति का आधार यहाँ की भाषा, बोली, पहनावा, आचार–विचार यहाँ की दैनिक दिनचर्या है।
- डा0 ज्योति रोहिल्ला राणा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने अपना व्याख्यान पूर्वान्चल की कला एवं सांस्कृतिक धरोहर पर प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्वान्चल की संस्कृति और परम्परा तथा उसकी ऐतिहासिकता अति प्राचीन है।
- डा0 बलराम शुक्ला, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडी, शिमला ने अपना व्याख्यान पूर्वान्चल की सांस्कृतिक विरासत विषय पर दिया और कहा कि पूर्वान्चल में शिक्षा को व्यवस्थित करके यहाँ की सुसंगत संस्कृति को संरक्षित किया जा सकता है।

तकनीकी सत्र–6

- प्रो0 सुजीत कुमार दूबे, बी0एच0यू0, वाराणसी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए बताया कि निम्न स्तरीय कौशल गरीबी को बढ़ाता है। उन्होने पूर्वान्चल की गरीबी के निवारण हेतु कौशल विकास से सम्बन्धित कोर्स की आवश्यकता पर बल दिया।
- प्रो0 डी0 साहू, बी0एच0यू0, वाराणसी ने व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे नयी शिक्षा नीति से जोड़ने पर विचार व्यक्त किया।
- डा0 डी0के0 मौर्या, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा स्किल डेवलपमेन्ट इन फ्लेक्सीबिल प्रिन्टेड इलेक्ट्रानिक्स के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया गया।
- डा0 तूलिका मिश्रा, इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग पर बल दिये जाने के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया गया।

तकनीकी सत्र–7

- श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा विभागीय की–नोट पेपर प्रस्तुत करते हुये विभागीय उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया गया तथा इसके साथ ही उनके द्वारा पूर्वान्चल के विकास हेतु आवास एवं शहरी नियोजन के सन्दर्भ में एक भावी विभागीय योजना का रोड मैप प्रस्तुत किया गया।
- प्रो0 भारत दहिया, निदेशक, थम्मासाट विश्वविद्यालय, बैंकाक, थाईलैण्ड द्वारा शहरी नियोजन के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत करते हुये शहरी नियोजन की वर्तमान स्थिति एवं विकास की सम्भावनायें एवं शहरी विकास हेतु भावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गयी। इसके साथ ही एस0डी0जी0 विजन–2030 पर प्रकाश डालते हुये पूर्वान्चल में शहरी विकास के लिये विकास कार्यक्रम संचालित करने पर बल दिया गया।
- डा0 प्रवीन पाठक, भूगोल विभाग, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा शहरी आवास के ज्वलन्त मुद्दे एवं चुनौतियों पर अपना उत्कृष्ट व्याख्यान प्रस्तुत करते हुये पूर्वान्चल में शहरी विकास से सम्बन्धित अनेक चुनौतियों को इंगित किया।
- डा0 ए0के0डी0 द्विवेदी, निदेशक, निलिट, गोरखपुर द्वारा पूर्वान्चल में विद्युत चालित वाहनों के विकास की सम्भावनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुये वाहनों के लिये बैटरी निर्माण का सुझाव दिया गया।
- श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 राज्यमंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में पूर्वान्चल में विकास की गति को तीव्र करने के लिये गुजरात मॉडल का अनुकरण करने का सुझाव दिया। इसके साथ उन्होंने अधिग्रहीत भूमि के सुनिश्चित उपयोग, भूमि सम्बन्धित विवादों का निपटारा, किरायेदारों के सम्बन्ध में लीज का पुनर्मूल्यांकन, प्लास्टिक के उन्मूलन, नगर निगम क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण एवं तत्सम्बन्धी जैविक खेती जैसे नवोन्मेषी विचारों से रोजगार की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में

विस्तृत विचार प्रस्तुत किये। इसके साथ ही उनके द्वारा नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र–8</u>

- डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा, विशेष सचिव, परिवहन विभाग द्वारा विभागीय की–नोट पेपर का प्रस्तुतीकरण करते हुये पूर्वान्चल क्षेत्र में परिवहन विकास के सन्दर्भ में एक भावी विभागीय योजना का रोड मैप प्रस्तुत किया गया।
- डा0 अशोक कुमार कैथल, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वान्चल क्षेत्र में परिवहन प्रणाली विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि यह क्षेत्र जनाधिक्य, निम्न आर्थिक विकास दर, चीनी मिलों के बन्द हो जाने के साथ–साथ कृषि यन्त्रीकरण के कारण बढ़ती बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहा है। इसके साथ ही उनके द्वारा पूर्वान्चल में आर्थिक क्रियाओं को और अधिक तीव्र करने के लिये सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विशेषकर परिवहन को विकसित करने का सुझाव दिया गया।
- श्री सैयद मसूद तथा श्री राजा जिसान, टाटा मोटर्स, लखनऊ द्वारा विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुये इसके विकास के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये गये।
- श्री आशीष कुमार, आई0सी0ए0टी0, गुड़गाँव ने अपने व्याख्यान में वाहन निरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये साथ ही गाड़ी फिटनेस सेन्टर एवं ड्राईवर फिटनेस पर विशेष बल दिया।
- डा0 मनीष हिन्दवी, विद्यान्त हिन्दू पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ ने पूर्वान्चल के विकास में संस्थागत वित्त की भूमिका पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि पूर्वान्चल में वित्त सम्बन्धी ऑकड़ों का अभाव है जिसे उचित माध्यमों से दुरूस्त करने की आवश्यकता है।
- श्री दिनेश तिवारी, रिलायन्स जियो, लखनऊ ने पूर्वान्चल में फाइबर टू द होम तकनीक विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इसके द्वारा टेलीकॉम आपरेटर्स के आय के स्रोतों को भी बढ़ाया जा सकता है और संचार सेवाओं की लागत को वहनीय बनाया जा सकता है।
- श्री एस0 नारायण, साहिबाबाद ने अपने व्याख्यान में बताया कि इलेक्ट्रानिक्स एवं आई0टी0 उद्योग में विकास की अपार सम्भावनायें हैं जोकि पूर्वान्चल के विकास में गेम चेन्जर के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- श्री रोहित तिवारी, एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर द्वारा पूर्वान्चल में दिहाड़ी मजदूरों की समस्याओं पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि इन मजदूरों को

निकटस्थ बाजारों में नियमित रोजगार न मिल पाने के कारण इनका रहन–सहन का स्तर अत्यन्त निम्न होता है ऐसे में उन्होंने लेबर हायर एप्लिकेशन को विकसित करने पर बल दिया।

<u>तकनीकी सत्र–9</u>

- श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने विभागीय की–नोट पेपर प्रस्तुत करते हुये पूर्वान्चल क्षेत्र में संस्थागत वित्त के विकास के सम्बन्ध में एक भावी विभागीय योजना का रोड मैप प्रस्तुत किया।
- प्रो मनोज कुमार मिश्रा, ब्रिटिश अमेरिकन विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा ने पूर्वान्चल के सामाजार्थिक विकास में संस्थागत वित्त की भूमिका विषय पर प्रस्तुतीकरण करते हुये पूर्वान्चल के विकास में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
- प्रो0 राजेश पाल, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल में ऋण जमा अनुपात पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में बहुत ही कम है। उन्होंने पूर्वान्चल में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम एवं आर्थिक विकास के माध्यम से संस्थागत वित्त तक पहुँच बढ़ाने के प्रयासों पर विशेष बल दिया।
- डा0 रमेश कुमार यादव, सहायक आर्थिक सलाहकार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में संस्थागत कृषि वित्त पर प्रस्तुतीकरण करते हुये पूर्वान्चल के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार, डिजिटल जागरूकता और क्रेडिट बाजार के बेहतर क्रियान्वयन के लिये आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के उपयोग पर अपना सुझाव प्रस्तुत किया गया।
- डा0 रजनीश मिश्रा, एमिटी विश्वविद्यालय, दुबई द्वारा प्रस्तुतीकरण करते हुये पूर्वान्चल में संस्थागत वित्त एवं वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति एवं प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गयी। इसके साथ ही उनके द्वारा सीमान्त एवं निम्न आय वर्ग के लोगों की वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेवाओं की पहुँच में तेजी लाने के लिये सरकार द्वारा संरचनात्मक एवं एकीकृत प्रयास पर जोर दिया गया।
- डा0 मनीष मिश्रा, कौशल विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा पूर्वान्चल में प्रसंस्करण समूहों के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये प्रशिक्षुकता एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया।
- डा0 मुर्तजा हुसैन, महानिदेशक, एन0आई0एस0जी0 हैदराबाद द्वारा अवगत कराया गया कि महामारी के बाद रोजगार एवं विकास को बढ़ाने के लिये रि–स्किलिंग बहुत ही सहायक और प्रभावी है।

- श्री राम कृष्ण शरण मणि त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार, गोरखपुर ने अवगत कराया कि पूर्वान्चल में पर्यटन एवं रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं। अतः पूर्वान्चल को पर्यटन हब के रूप में विकसित करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी

पूर्वांचल का सतत विकास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक पहल

मुद्दे, रणनीति एवम् भावी दिशा

10-12 दिसम्बर, 2020

सामाजिक क्षेत्र

कार्यक्रम स्थल : बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग भवन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर-273009 (उ.प्र.)

आयोजक

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

<u>सामाजिक क्षेत्र</u>

<u>पृष्ठभूमि</u>

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक विकास में चिकित्सा एवं शिक्षा का विकास होना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिये स्वस्थ होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा तो मन–मस्तिष्क स्वस्थ होगा तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तभी वह उचित प्रयत्न कर विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वान्चल में चिकित्सीय सेवाओं के उत्थान के लिये निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिये नयी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं तथा उपलब्ध स्वास्थ्य केन्द्रों को नवीनतम उपकरणों से आच्छादित किया जा रहा है।

शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी एवं वर्तमान भौतिक युग में आर्थिक स्तर ऊँचा होने का द्योतक है। पूर्वान्चल की भौगोलिक सीमा में शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस प्रक्रिया में प्रायः प्रत्येक नियमित अन्तराल पर विभिन्न स्तर के संस्थान खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु विभिन्न विकास विभागों यथा–समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्राम्य विकास तथा महिला कल्याण आदि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वेबिनार में किये गये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी सत्रवार स्थिति निम्नवत् हैः–

<u>तकनीकी सत्र–1</u>

- तकनीकी सत्र में 6 शोध पेपर प्रस्तुत हुये जिसमें रोगों, इसके प्रसार एवं समाधान से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा हुई। मुख्य मुद्दे यथा– वेक्टर और जल जनित रोगों और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता की कमी, SARS, COVID-19 और उनके नैदानिक उपकरणों को संशोधित करने की आवश्यकता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुदृढ़ीकरण, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का प्रोत्साहन आदि उभरकर आये। इस सत्र में मुख्य रणनीतियाँ/समाधान निम्नवत् उभरकर आयेः–
  - ➢ स्थानीय निकायों को सम्मिलित करके जागरूकता को बढ़ावा देना।
  - ➢ डायग्नोस्टिक्स से सम्बन्धित चिकित्सा उपचार और आयुर्वेद से सम्बन्धित पारम्परिक/स्वदेशी ज्ञान आम जनता को पहुंचाना तथा दैनिक जीवन में उपयोग करने के तरीके से अवगत कराना।

- स्वास्थ्य जागरूकता को स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना ताकि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का भार कम हो।

<u>तकनीकी सत्र–2</u>

- श्री अतुल गर्ग, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में इन्सेफ्लाईटिस जैसी विभिन्न बीमारियों के कारण बच्चों की मृत्यु दर में कमी आने के बारे में अवगत कराते हुए एम0बी0बी0एस0 जैसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने स्तर से बुनियादी ढाँचे को विकसित करने हेतु सुझाव दिया गया।
- श्री एन0सी0 प्रजापति, प्रतिनिधि, डी0जी0एम0ई0 द्वारा दन्त चिकित्सा, नर्सिंग कालेजों में मैन पावर की कम संख्या, चिकित्सा शिक्षकों की कमी, पी0जी0 प्रदान करने वाले बहुत कम संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों एवं भावी दिशा–निर्देशों से अवगत कराते हुये कहा कि मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कालेजों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन, संविदा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, एम0आर0 और जूनियर रेजिडेंट की स्टाइपेंड में वृद्धि, पी0जी0 की शुरूआत और स्कूल कालेजों में मनोरंजन के लिये सुधार विषयक सुविधायें बढ़ाये जाने पर जोर दिया।
- डा0 दिनेश कुमार यादव, प्राचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा कोविड–19 महामारी युग में पूर्वांचल के लोगों की बहुत कुशलता से सेवा किये जाने से अवगत कराया गया।
- डा0 सुशील कुमार द्वारा जठरांत्र सम्बन्धी रोगों के बारे में चर्चा करते हुए इसकी रोकथाम के लिए स्वच्छ भोजन एवं शुद्ध पेय जल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र–3</u>

- श्री रमापति शास्त्री, मा0 मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना किये जाने तथा जनपद गोरखपुर को यथाशीघ्र हाईटेक सिटी बनाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
- श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण द्वारा नेपाल सीमा के पास रहने वाले 15 लाख आदिवासी लोगों के जीवन को प्रोत्साहन विषयक राज्य सरकार के प्रयासों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
- प्रो0 कल्पलता पाण्डेय, कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा को स्थानीय भाषा में प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया।

- प्रो0 आई0एस0 विश्वकर्मा, अध्यक्ष, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा लोगों को उच्च शिक्षा और उत्थान के लिए आयोग द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में अवगत कराया।
- निदेशक, समाज कल्याण ने पूर्वी उ0प्र0 में सामाजिक सुरक्षा नीतियों का वर्णन किया।
- प्रो0 एम0के0 वर्मा, पूर्व प्रमुख, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ द्वारा पर्यावरण के मुद्दे, वायु प्रदूषण, बाजार मूल्य पर पुर्नवास आदि को प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी सत्र–4

- श्री मनोज कुमार राय, निदेशक, महिला कल्याण द्वारा लिंग सम्बंधित विभिन्न मुद्दों यथा–महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका, शिक्षा के लिये बालिकाओं को सभी प्रकार के समान अवसर आदि पर चर्चा की गयी।
- प्रोफेसर नंदिता आई0पी0सिंह, डीन, आर्ट फैकल्टी ने पुरूष और महिलाओं के लिए लिंग संवेदीकरण, कार्य स्थल पर उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों आदि विषयों पर जानकारी दी गयी।
- श्री अनिल सिंह, सदस्य, कार्यकारी परिषद ने किसानों की स्थितियों में सुधार हेतु सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।

तकनीकी सत्र–5

- श्री अनिल राजभर, मा0 मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सत्र की अध्यक्षता की गयी।
- श्री हेमंत राव, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकलांगों को विभिन्न स्तरों पर दी जा रही विविध सुविधाओं के विषय में जानकारी दी गयी।
- डा0 नरेश त्रिखा, पूर्व निदेशक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव द्वारा पांच साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त एवं रूग्णता के सम्बंध में किये गये अध्ययन के सम्बंध में अवगत कराया गया कि जिंक न केवल दस्त के मामले में अपितु अन्य बीमारियों जैसे कि कोविड–19 से प्रतिरक्षा में सुधार करता है। ओ0आर0एस0 निर्जलीकरण के मामले को कम करता है। जिंक व ओ0आर0एस0 दोनों पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त के कारण होने वाली रूग्णता में जोखिम को कम कर सकते हैं।
- डा0 अनूप कुमार, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने प्रदेश सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में डेढ़ लाख दिव्यांगजनों की पहचान करके उन्हें विविध सुविधाएं उपलब्ध कराने के विषय में अवगत कराया।
- प्रो0 संजय तिवारी ने भारत की पैरा ओलम्पिक समिति की चर्चा करते हुए इस पर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बतायी।

<u>तकनीकी सत्र–6</u>

- श्री सतीश द्विवेदी, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सत्र की अध्यक्षता की गयी, जिसमें उनके द्वारा शिक्षा के सम्बंध में किये गये प्रयासों से अवगत कराया गया।
- श्री विजय किरन आनंद, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा स्मार्ट क्लासेस सिस्टम को बढ़ावा देने तथा छात्रों को सकारात्मक माहौल देने की आवश्यकता दर्शायी गयी। निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए दीक्षा एप पर चर्चा की गई तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तरों पर छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु बल दिया।
- सुश्री सुषमा पाण्डेय, शिक्षा विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की उपस्थिति और महिला शिक्षकों की उपलब्धता पर ध्यान दिये जाने का सुझाव दिया गया।
- श्री महेन्द्र कुमार सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा अनुसंधान एवं कौशल उन्मुख शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने का सुझाव दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र–7</u>

- श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन करना है। इसके साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र में शैक्षिक सुधारों को लागू करने तथा सकल नामांकन दर को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अवगत कराया कि प्रदेश सरकार पिछड़े क्षेत्रों में 11 सरकारी डिग्री कालेज खोलने जा रही है तथा ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ाये जाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोलने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि पी0पी0पी0 मॉडल पर ई–लर्निंग पार्क की स्थापना होगी तथा कौशल विकास के लिये सभी तकनीकी संस्थान व एम0एस0एम0ई0 विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जायेगा।
- डा0 गोपाल प्रसाद, राजनीति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से सम्बन्धित छात्रों की बेहतरी के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, मोहल्ला पाठशाला तथा सामुदायिक पुस्तकालय पर चर्चा की।
- डा0 अमित भारद्वाज, निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू करते हुए अवगत कराया कि पूर्वान्चल क्षेत्र में छात्र–शिक्षक अनुपात बहुत कम है और प्रदेश सरकार इस स्थिति पर गम्भीरता से काम कर रही है।

- डा0 राज शरण शाही, एसोसिएट प्रोफेसर, दिग्विजयनाथ पी0जी0 कालेज, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अधिक सटीकता के साथ उचित मूल्यांकन प्रणाली विकसित किये जाने हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाना होगा।
- डा0 प्रज्ञा मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता बहुत खराब है इसके लिए उन्होंने एकीकृत समाधान का भी सुझाव दिया।

तकनीकी सत्र–8

- डा0 एन0के0 चौधरी, आर0एम0एल0 अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर नये नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही नियोक्ता और श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखे जाने पर बल दिया गया। उन्होंने नौकरी के अवसरों के लिये तकनीकी क्षेत्र में युवाओं की अपर्याप्त योग्यता जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया।
- प्रो0 सत्य प्रकाश पाण्डेय, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़ द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुसंधान और विकास पहल पर प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि विकास का ऊर्जा से सीधा सम्बन्ध है और बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी उन्नयन की अधिक आवश्यकता है। इसके साथ उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि एक जिला एक उत्पाद की धारणा को पूरा करने हेतु स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- डा0 जयति त्रिवेदी, सीनियर साइन्टिस्ट, सी0एस0आई0आर0 ने ''गाँव–गाँव में बायोडीजल'' विषय पर प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया कि खाना पकाने का तेल बायोडीजल का एक सम्भावित क्षेत्र है। इसके उत्पादन के व्यवसायीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।
- प्रो0 एस0एन0 सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमें टिकाऊ कृषि की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा में उच्च गिरावट है जिसे गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। नौकरी चाहने वाले होने के स्थान पर हमें नौकरी सृजक बनना चाहिये।

तकनीकी सत्र–9

- श्री सूर्य प्रताप शाही, मा0 मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की नीतियों को राज्य में लागू करने के तरीके पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। वर्तमान बजट में कृषि गतिविधियों के लिए अधिक आशाजनक योजनाएँ है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं किसानों को अनुदानित सहायता से अवगत कराया।

- डा0 आर0सी0 चौधरी, पी0आर0डी0एफ0 गोरखपुर द्वारा ''पूर्वान्चल में स्वास्थ्य, धन और रोजगार के लिए जैव उर्वरक फसलों को बढ़ावा'' विषय पर प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और शहरी क्षेत्रों में आयरन और विटामिन–ए की कमी से पीड़ित है। उन्होंने गरिष्ठ भोजन को बढ़ावा देने और पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग के साथ–साथ 'विटामिन–ए' के स्रोत के रूप में गोल्डन स्वीट पोटैटो की खेती के लिये सुझाव दिया।
- प्रो0 संगीता पाण्डे, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा ''महिला किसानों के सशक्तिकरण'' विषय पर प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्तिहीन अपने जीवन की परिस्थितियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। उन्होंने महिला किसानों की संकीर्ण धारणा को बदलने पर जोर दिया।
- ले0 कर्नल कृष्ण मुरारी लाल, फाउन्डेशन फार सोशल वेलफेयर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल क्षेत्र में डेरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। खेती को छोड़कर हर परिवार को एक और व्यवसाय करना चाहिए। सरकार को युवाओं के कौशल विकास और आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढ़ाचे के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी

पूर्वांचल का सतत विकास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक पहल

मुद्दे, रणनीति एवम् भावी दिशा

10-12 दिसम्बर, 2020

कार्यक्रम स्थलः प्राणि विज्ञान अनुसंधान भवन, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ.प्र.)

आयोजकः

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

जल क्षेत्र

पृष्ठभूमि

लगभग 1980 के दशक के बाद वैश्विक जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक–आर्थिक विकास और बदलते उपभोग के स्वरूप के कारण पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग एक प्रतिशत की दर से पानी के उपयोग में वृद्धि दर्ज की गई है (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, 2019)। आज औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में बढ़ती मॉगों के कारण जल का उपयोग ज्यामितीय दर से बढ़ा है। लाखों लोग जलापूर्ति की कमी के साथ जीवन जीने को मजबूर हैं। जल की बढ़ती मॉग तनाव के स्तर को और बढ़ाएगी और बिना किसी संदेह के जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को तेज करेगी।

भारत का विशाल क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण वर्ष भर कृषि के लिए अनुकूल है। इस हेतु कृषि भूमि से वाष्पीकरण/वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर को पूरा करने के लिए जल के वर्ष पर्यन्त स्रोत की आवश्यकता है। उत्तरी भारत में गंगा के मैदानी मार्ग में तेजी से बढ़ती आबादी (साथ ही अन्य कारक) के कारण यह क्षेत्र भविष्य में जल की कमी के लिए उच्च जोखिम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र भी भारत में गंगा के मैदानी भाग में स्थित है और पश्चिमी बिहार के साथ सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसे ''पूर्वान्चल क्षेत्र'' के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में जल में बढ़ती मॉग के लिए रणनीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय वेबिनार में किये गये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी सत्रवार स्थिति निम्नवत् हैः–

तकनीकी सत्र–1

- डा0 महेंद्र सिंह, जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पानी का संरक्षण समय की जरूरत है। राज्य सरकार जल्द ही वर्षा जल संचयन के लिए एक कानून पेश करेगी। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए हर घर नल योजना शुरू की गयी है। जल्द ही पूर्वांचल सहित अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा।
- श्री ए0के0 सिंह, इंजीनियर इन चीफ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा Challenges, Solutions and way forward for Sustainable water Resource Management in Poorvanchal विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें पुरानी सिंचाई प्रणाली को बदलने, नदियों के बहाव को नियंत्रित करने हेतु चैनलाइजेशन, सिल्ट वेन/बॉटम पैनल इत्यादि कार्य किये जाने एवं उच्च उत्पादकता वाली फसलों हेतु अधिक पानी की आवश्यकता तथा नहरों के माध्यम से असमान जल वितरण से सम्बन्धित बिन्दुओं के समाधान हेतु सुझाव दिये गये।

- श्री अनिल सिन्हा, सीनियर एडवाइजर, 2030 WRG द्वारा Role of Integrated Multi Stake Holder Approach For Collective Action in Water Sector विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें Decentralized waste water Treatment की आवश्यकता तथा बाढ़, जलभराव, सूखा के निदान हेतु सरकारी एवं निजी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- श्री अनुज श्रीवास्तव, एस0वी0एस0एस0, एन0जी0ओ0 द्वारा Role of Public Management Addressing Water Challanges विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें जल चुनौतियों के सम्बन्ध में जन आन्दोलन की भूमिका की आवश्यकता जल चौपाल के माध्यम से किये जाने पर बल दिया गया।
- डा0 वेंकटेश दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ द्वारा Water Management and Challenges in U.P Policy Initiatives and Strategies for Resilience विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें उन्होंने बाढ़ की समस्या, जल की कमी तथा रिवर बेसिन प्लानिंग के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये।
- डा0 दीपक प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा Water Crisis in Poorvanchal Region: A Geographical Analysis of Uses, Challenges And Prospects के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें मौसम के अनुसार जल की गहराई में परिवर्तन तथा औद्योगिक कचरों से युक्त पानी को सीधे नदी में गिराने आदि के निराकरण के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये।

<u>तकनीकी सत्र–2</u>

- इस सत्र में डा0 एम0के0 निगम, चीफ इंजीनियर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग गोरखपुर, अखिलेश कुमार सिंह, चीफ इंजीनियर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कर्नल एस0जी0 दलवी, पुणे, प्रो0 आर0पी0 यादव, भूतपूर्व प्राचार्य, जनता पी0जी0 कालेज, मऊ तथा डा0 राजेश यादव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- विन्ध्यांचल क्षेत्र के वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु बड़े बांध बनाना उपयोगी होगा।
- गंडक, शारदा सहायक प्रणाली में बनी हुई संरचनाओं की पुनरोद्धार की आवश्यकता।
- हिमालय से निकलकर पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाली नदियों से सिल्ट की समस्या होना।
- सिंचाई एवं बाढ़ प्रबन्धन में पूर्व निर्मित संरचनाओं का आधुनिकीकरण किया जाना।
- रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन पर बल देना।
- जल संरक्षण नीति की आवश्यकता।
- बाढ़ के प्रभाव को कम करने हेतु उपाय।

- पुरानी पाइप लाइन होने के कारण पानी के ट्रांसपोर्टेशन में जल का ह्रास होता है इसमें सुधार की आवश्यकता है।

<u>तकनीकी सत्र–3</u>

- इस सत्र में डॉ विजय कुमार सिंह, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन वाटर, गोरखपुर, प्रो0 मनिन्द्र अग्रवाल, आई0आई0टी0 कानपुर, प्रो0 वीना वी0 कुशवाहा तथा प्रो0 अनिल कुमार द्विवेदी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा विचार व्यक्त किये गये।
- पूर्वांचल क्षेत्र में बाढ़, जल प्लावन, भूगर्भ जल एवं सतही जल में प्रदूषण तथा विन्ध्यांचल क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र की समस्या है। अतः भूमिगत जल का दोहन प्रबन्धन, पर्यावरण सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन हेतु जनमानस में जागरूकता, हाइड्रोपोलिक्स टेक्नोलॉजी से गमलों में प्लांट्स को न्यूट्रिएण्ट्स और पानी द्वारा शाक–सब्जी का उत्पादन तथा दूषित जल को पारम्परिक तकनीक द्वारा साफ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

<u>तकनीकी सत्र–4</u>

- श्री अनुपम, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग ने अवगत कराया कि भूजल में आर्सेनिक की समस्या है तथा भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। अतः पूर्वान्चल के समस्त विकासखण्डों में मल्टीपल मानीटरिंग नेटवर्क की आवश्यकता है।
- डा0 राम आशीष यादव, भूतपूर्व मैनेजर, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूषित पेयजल के बारे में जनमानस को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।
- प्रो0 गोविन्द पाण्डेय, डीन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि भारत अतिशीघ्र जल प्रभावित राष्ट्र की श्रेणी में आने वाला है। अतः भूगर्भ जल के स्थान पर सतही स्रोतों पर ज्यादा निर्भरता होनी चाहिए। इसके साथ ही जल को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु जनसमुदाय को प्रेरित करने, वनीकरण को बढ़ाये जाने, कम गहराई में लगे पम्पों को ठीक किया जाना तथा समग्र भूजल प्रबन्धन योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

<u>तकनीकी सत्र–5</u>

- श्री विप्लब पाल, निदेशक, भुगरू, एन0जी0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्था, भुगरू द्वारा जल फौजी का प्लान तैयार किया है जिसे जल प्लावित क्षेत्रों, अतिदोहित क्षेत्रों तथा शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है।
- श्री अमित मिश्रा, वसार लैब द्वारा अवगत कराया गया कि जल सुरक्षा योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

- प्रो0 एच0के0 पाण्डेय, एम0एन0–एन0आई0आई0टी0, इलाहाबाद ने अवगत कराया कि पूर्वांचल में कई गांव में अभी भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नही है तथा फ्लोराइड की अधिकता होने से बीमारी भी हो रही है। पेयजल से आर्सेनिक की मात्रा दूर करने के लिए चिन्हित ग्रामों में फिल्टर उपलब्ध कराने चाहिए तथा औद्योगिक कचरे के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- डा0 विनोद कुमार चौधरी, आर0एम0एल0 अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा गंगा नदी के किनारे दाह संस्कार स्थलों को विकसित करने, पर्यटक सौन्दर्यशास्त्र तथा पूर्वी क्षेत्र में नदियों की जल की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- डा0 एस0के0 श्रीवास्तव, ए0पी0पी0ओ0, एन0जी0ओ0 द्वारा लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रयोग करने की आवश्यकता तथा इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा विकासखण्ड स्तर पर अनुश्रवण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- सुश्री बुशरा वारसी, रिसर्च स्कालर, गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा अधिक पेड़ लगाये जाने, औद्योगिक प्रदूषण के लगातार अनुश्रवण, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट तथा वाटर रीयूज एण्ड रीसाइक्लिंग की आवश्यकता बताई गयी।

<u>तकनीकी सत्र–6</u>

- इस सत्र में श्री जेवियर चौराट, वर्ल्ड बैंक, डा0 अंशुमान, एसोसिएट डायरेक्टर, टी0ई0आर0आई0, नई दिल्ली, ई0 आर0सी0 तिवारी, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या तथा डा0 टी0पी0 यादव, बी0एच0यू0, वाराणसी द्वारा प्रतिभाग कर निम्न सुझाव दिये गयेः–
  - जल के उपभोगकर्ताओं के मध्य संतुलित वितरण हेतु डेटा बेस तैयार करना।
  - भूगर्भ जल का संतुलित प्रबंधन।
  - जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रोत्साहन देना।
  - स्वच्छता प्रबंधन हेतु सहयोग प्रदान करना।
  - भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन पर विचार करना।
  - जल के दुरूपयोग पर नियंत्रण करना।
  - निरन्तर जल पर्यवेक्षण।
  - उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले जल के नियंत्रण पर विचार करना।
  - स्वच्छ जल हेतु Nano Tulee Filteration का उपयोग।

<u>तकनीकी सत्र–7</u>

- इस सत्र में प्रो0 रवि शंकर सिंह, कुलपति, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, श्री रमाकान्त तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गोरखपुर, श्री के0

रविन्द्र नायक, आयुक्त, मनरेगा, उ0प्र0, डा0 अनिल कुमार तिवारी, के0डी0बी0 कॉलेज, बलिया तथा डा0 सुभाष यादव, आर्कियोलाजिकल आफिसर, वाराणसी द्वारा प्रतिभाग किया गया। **इस सत्र में प्रमुख रूप से निम्न सुझाव दिये गयेः–**

- पूर्वान्चल में मानसून के समय बाढ़ की समस्या एवं गर्मी में सूखे की समस्या सामान्यतया रहती है। अतः इसके निदान हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आवश्यक है।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सभी स्तर पर अनिवार्य एवं कड़े कानून बनाने की जरूरत के साथ ही इसके लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने की भी आवश्यकता है।
- बिजली की कमी एवं डीजल का खर्च ज्यादा होने के कारण सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा का निःशुल्क बोरिंग योजना एवं अन्य योजना में उपयोग किया जा सकता है।
- आपरेशन चतुर्भुज लखीमपुर माडल को पूर्वान्चल क्षेत्र में रेप्लीकेट करने की आवश्यकता है।

<u>तकनीकी सत्र–8</u>

- सत्र में प्रो0 एन0बी0 सिंह, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा तथा डा0 अखिलेन्द्र नाथ तिवारी, भूगोल विभाग, एस0बी0पी0 कालेज, भबुआ, बिहार द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस सत्र के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न सुझाव दिये गयेः–
  - वाटर क्वालिटी टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं रेवन्यू सुविधाओं को डिजिटाइज्ड करने की आवश्यकता है।
  - अटल मिशन फार रेजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन की गाइड लाइन्स का पालन कर अप्रेजल और गैप असेसमेन्ट को ज्ञात करके इसके निदान हेतु स्थानीय लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है।
  - सभी परिवारों के आवास में स्थित शौचालयों को सीवर से जोड़ने हेतु सम्बन्धित अथारिटी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
  - अस्वच्छ पानी के उपयोग से होने वाली बीमारियों के निदान में काफी धन खर्च होता है। अतः जल को स्वच्छ बनाकर उपभोग में लाने से बीमारियों में कमी के साथ ही धन की बचत की जा सकती है।
  - सबमर्सिबिल पम्प एवं हैण्ड पम्प के उपभोग को कुछ प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ अनुमति दी जानी चाहिए।
  - पानी की सप्लाई में प्रतिबन्ध होना चाहिए। इसके साथ ही पेयजल को बर्बाद होने से बचाने के प्रयास भी करने की आवश्यकता है।

तकनीकी सत्र–9

- इस सत्र में श्री जी0 अशोक कुमार, एम0डी0, नेशनल वाटर मिशन, प्रो0 एम0एन0पी0 तिवारी, बी0एच0यू0, वाराणसी, Mr. Ijsbrand de jong, Lead, WRM, Specialist, World Bank तथा श्री कृष्णा त्यागी, जी0आई0जेड0 कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस सत्र के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न सुझाव दिये गयेः-

- सिंचाई क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है।
- सिंचाई तकनीक की नई पद्धतियों का उपयोग करके आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है।
- इन्टीग्रेटेड वाटर रिसोर्सस मैनेजमेन्ट में ब्राजील और फ्रांस के माडल को एडाप्ट करने की आवश्यकता है जो विश्व की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार इरीगेशन मैनेजमेन्ट पर फ्रांस के माडल को एडाप्ट करने की आवश्यकता है।
- नदियों को प्रदूषण मुक्त एवं साफ रखने हेतु जो वैज्ञानिक प्रयास किये जा रहे हैं, उसके साथ ही हमें गंगा के प्रति आस्था एवं उसकी पवित्रता से भी बोध कराना चाहिए जिससे लोगों के मन में इसके संरक्षण एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो।
- जल योजनाओं का सामुदायिक सहभागिता से निर्माण।

<u>विशेष सत्रः सामूहिक संगठनों से सम्बन्धित</u>

- श्री नवनीत कुमार सहगल, अपर मुख्य सचिव, एम0एस0एम0ई0 विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 के क्षेत्र और योजनाओं में किये जा रहे प्रमुख कार्यों पर जोर देने के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन और गुणवत्ता पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता को दर्शाते हुए इसके लिए सम्बन्धित तकनीकी सहायता एवं मशीनरी की मांग के विषय में अवगत कराया गया।
- प्रो0 रामचेत चौधरी, चेयरमैन पी0आर0डी0एफ0, कृषि वैज्ञानिक, गोरखपुर ने जैविक काला नमक चावल के लगातार उत्पादन तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मुनाफे तथा रोजगार का उल्लेख किया।
- श्री बी0एम0 त्रिपाठी, सचिव, एस0एच0डी0ए0, गोरखपुर ने प्याज और हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता बतायी।
- डा0 अंबरीश गौड़, फैशन डिजाइन विभाग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर ने पूर्वान्चल क्षेत्र में खत्म हो रहे शिल्प को पुनर्जीवित करने के साथ वन ब्रांड, वन आइडेंटिटी पर जोर दिया तथा स्थानीय प्रस्तुतियों के लिये वैश्विक मंच प्रदान करने की बात की।
- श्री उमेश कुमार प्रजापति, टेराकोटा कारीगर ने टेराकोटा आइटम को विभिन्न स्थलों तक ऑनलाईन पहुंचाने के लिये पैकेजिंग की समस्या पर ध्यान दिलाया।
- श्री रवि प्रसाद, हैण्डीक्राफ्ट उद्यमी, कुशीनगर ने केले के पेड़ को कचरे में बदलने व केले से फाइबर तैयार करने के साथ वहाँ स्थानीय लोगों की कमी पर चर्चा की।
- श्री मनोज कुमार, सहायक शिक्षक, मुरारी इंटर कालेज, गोरखपुर ने टेराकोटा की मूर्तियाँ तैयार करने में विभिन्न तापमान की चर्चा की।
- डा0 आनन्द मिश्रा, निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग ने एस0डी0जी0 के विषय में चर्चा की।

  चर्चा में निम्न बिन्दु उभरकर आयेः—

  - प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं में जागरूकता को सुनिश्चित करना।
  - किसानों के मध्य प्रभावी कृषि तकनीकों, बीजों की गुणवत्ता, फसलों के विपणन के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  - विशेष समूहों की क्षमता और योग्यताओं को चैनेलाइज कराना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश में सुधार करने की आवश्यकता।
  - पूर्वांचल क्षेत्र में विशेष समूहों के लिए जनसुविधा केन्द्रों एवं स्वंयसेवी संगठनों को बढ़ाने की आवश्यकता।
  - किसानों के पक्ष में लाभ बढ़ाने के लिए इनपुट लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता।
  - छोटे एवं मध्यम उद्योगों के कारीगरों के जीवन में व्यापक आर्थिक एवं सूक्ष्म स्तर की समस्याओं का समाधान।

विशेष सत्रः पूर्वान्चल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन (स्पेशल पैकेज फॉर पूर्वान्चल)

- सत्र में श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, प्रोफेसर श्रीवर्धन पाठक, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डा0 बृंद कुमार, आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 तथा सरकारी आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित उद्यमियों आदि ने प्रतिभाग किया।
- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ने पूर्वान्चल के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परियोजनाओं का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हुए शासन को और अधिक अनुदान दिये जाने पर विचार करने का सुझाव दिया गया।
- श्री पंकज कुमार सिंह, जन सम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे की पूर्वान्चल केन्द्रित विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा करते हुए पूर्वान्चल के विकास हेतु इसे आधार के रूप में प्रस्तुत किया।
- डा0 ए0के0 सिंह, एम0एल0एन0आई0टी0, प्रयागराज ने आधारभूत संरचनागत प्रबन्धन में 3D मैपिंग और जी0आई0एस0 तकनीक के उपयोग पर प्रकाश डाला गया।
- सरकारी आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित मधुमक्खी पालक उद्यमी श्री निमित सिंह, रेडीमेड वस्त्र उद्योग के उद्यमी श्री धर्मेन्द्र भारती इत्यादि द्वारा सरकारी विशेष आर्थिक प्रोत्साहनों को वृहद स्तर पर लागू किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।

विशेष सत्रः बैकिंग क्षेत्र

- श्री सुरेश खन्ना, मा0 मंत्री, वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा भूमिहीन एवं हुनरमंद लोगों को विकसित करने, बैंकों को कार्ययोजना बनाकर कार्य करने, स्वयं सहायता समूहों का बैंकों द्वारा खाता खोले जाने, बैंकिग समिति बनाकर लोगों को साक्षात्कार के माध्यम से लोन देने आदि पर जोर दिया गया।
- श्री साकेत मिश्र, माननीय सलाहकार, पूर्वान्चल विकास बोर्ड द्वारा विकास को सांख्यिकीय रूप में मापन न करके स्वयं कार्य किये जाने पर जोर देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्टार्टअप कार्यक्रम को डिजीटाइज करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता बतायी गयी। इसके साथ ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया में परिवर्तन कर उद्योगपतियों को कम ब्याज दर पर सम्पत्ति खरीदने के लिए ऋण देने पर जोर दिया गया।
- श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा बैकिंग समिति की सतत् बैठक सुचारू रूप से करने, पूर्वान्चल में ऋण–जमा अनुपात को बढ़ाने तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अधिक से अधिक उद्यमियों को आच्छादित करने पर जोर दिया गया।
- श्री डी0पी0 ग्रोवर, अध्यक्ष, बड़ौदा यू0पी0 बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पी0एम0रोजगार योजना एवं पी0एम0किसान योजना में रोजगार के अवसर को बढ़ाने, बैंकर्स को मिलकर ऋण–जमा अनुपात में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर ऋण हेतु प्रचार करने पर जोर दिया गया।
- श्री विनोद कुमार, ए0जी0एम0, इंडियन बैंक, इलाहाबाद द्वारा ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर उद्योग को बढ़ावा देने, पी0एम0सुरक्षा एवं जीवन ज्योति योजना में प्राप्त हो रहे प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किये जाने के साथ डिजिटल अपग्रेडेशन के कार्य को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- श्री बृजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा द्वारा जन सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं में छोटे–छोटे खाते खोले जाने, वन टाइम सहयोग प्रदान कर पुनः लोनिंग करने तथा के0सी0सी0 का शत–प्रतिशत संतृप्तीकरण हेतु डिजिटल पोर्टल लान्च करने पर बल दिया गया।
- श्री ए0के0 झा, उप महाप्रबंधक, इंडियन बैंक, गोरखपुर द्वारा पानी, बिजली सड़क का विकास मानक के अनुसार किये जाने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने पर बल दिया गया।
- श्री अवनिन्द्र सिन्हा, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल द्वारा कृषि आधारित रोजगार योजनाओं तथा बैंक के माध्यम से आर्थिक विकास किये जाने पर बल दिया गया।
- श्री मनीष प्रथपाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, गोरखपुर द्वारा पंजाब की तरह किसानों के लिए तकनीकी उपकरण का उपयोग करने तथा अन्य अप्रयोज्य भूमि को उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया।
- श्री भोला प्रसाद, उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, गोरखपुर द्वारा बैंकों के माध्यम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया।

विशेष सत्रः औद्योगिक क्षेत्र

इस सत्र में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयीः—

- प्रो0 रितेश कुमार सिंह, डीन, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर दिया।
- श्री आर0के0 शर्मा, उपायुक्त, उद्योग, गोरखपुर ने आई0आई0ई0पी0पी0 के संदर्भ में निवेश के लिए प्रमुख मुद्दों, नीतियों और योजनाओं के बारे में चर्चा की।
- श्री अब्दुल राशिद, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, वाणिज्य कर, जी0एस0टी0, गोरखपुर ने उन रणनीतियों पर प्रकाश डाला कि कैसे आसानी से और आराम से किसी भी व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। उन्होंने स्टार्ट—अप के लिए विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया।
- श्री वी0पी0 अजीतसरिया, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, गोरखपुर ने हथकरघा की हमारी परम्परा को बनाए रखने के लिए 'लोकल फॉर वोकल' की आवश्यकता के बारे में चर्चा की, जिसे पावरलूम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- श्री एस0के0 अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, गोरखपुर ने बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कहा कि जिसके कारण विभिन्न उद्योगपतियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- श्री विजय पांडे, अध्यक्ष— एच0आर0, अमलगम स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न स्थायी सुधार नीतियों के बारे में चर्चा की।
- श्री आर0एन0 सिंह, उपाध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, गोरखपुर ने सूक्ष्म उद्योगों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं का उल्लेख किया।
- श्री प्रवीण मोदी, जनरल सेक्रेटरी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी व्यापार करने में आसानी के लिए सुशासन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
- प्रो0 नंदिता सिंह, डीन, कला संकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने टेराकोटा मूर्तियों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए उचित विपणन जोखिम पर बल दिया। उन्होंने पारंपरिक उत्पादों के लिए नए डिजाइन विचारों को विकसित करने तथा स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की आवश्यकता भी बतायी।

इस सत्र में विचार—विमर्श के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र हेतु निम्न सुझाव उभरकर आये :—

- कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक समावेशी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता।

- 4 M's यानि मैन, मनी, मशीन और मार्केट का क्लस्टर बनाने की आवश्यकता।
- 'रिवर्स माइग्रेशन' को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां और रणनीतियाँ।
- सतत् व्यापार सुधार और सुशासन नीतियों पर जोर दिया जाना।
- उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कुशल मानव–संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधा की जरूरत।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से कच्चे माल को ले जाने और उत्पादों को अपने बाजारों तक पहुँचाने के लिए पूर्वांचल को एक्सप्रेस–वे मार्ग से जोड़ने के प्रयासों को पूरा करना।
- विश्व स्तर के होटल, हवाई अड्डे और प्राथमिक और उच्च शिक्षा केंद्र विकसित करने के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता।
- अत्याधुनिक अनुसंधान, परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता।
- सेवा क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता।
- पूर्वांचल को आई0टी0 हब के रूप में विकसित करना।
- कई SEZs विकसित करने की आवश्यकता है।
- भूमि बैंक विकसित करने के लिए औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता।
- कम कागज के काम के साथ आसान ऋण के लिए नीतियों की आवश्यकता।

विशेष सत्रः खेल

- खेल अर्जुन अवार्डी और पूर्व निदेशक (खेल) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय डा0 दलेल सिंह चौहान ने खेल के विशेष सत्र में कहा कि पूरे देश में लगभग 75 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में एक पूर्ण खेल विभाग नहीं है। योग्य प्रशिक्षकों और शिक्षकों की भारी कमी है। विश्वविद्यालय में खेल विभागों के लिए वित्तीय व्यवस्था का भी अभाव है। यह भी आवश्यक है कि हम मानसिक परिवर्तन करें और इस अभियान को पूरे क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के लिए एक सार्थक पहल बनाएं।
- डा0 आर0एन0 सिंह, उप निदेशक (खेल), बी0एच0यू0, वाराणसी और पूर्व निदेशक (खेल) डा0 हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर ने पूर्वांचल में खेलों के विकास के संबंध में अपने विचार और अनुभव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि हमें जलग्रहण क्षेत्र और सामाजिक–आर्थिक और सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति का आंकलन करना होगा, क्योंकि इसके बिना हम अच्छी स्थिति में खेलों का विकास नहीं कर सकते।

<u>समापन सत्र</u>

- समापन सत्र का आयोजन दिनॉक 12.12.2020 को अपरान्ह 04.00 से दीक्षा भवन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में किया गया।
- समापन सत्र में मुख्य अतिथि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, विशिष्ट अतिथि श्री श्रीपद नाईक, मा0 आयुष मंत्री, भारत सरकार, पूर्वान्चल विकास बोर्ड के मा0 उपाध्यक्षगण, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति तथा प्रमुख सचिव, नियोजन थे।
- श्री श्रीपद नाईक, आयुष मंत्री, भारत सरकार तथा प्रो0 डी0पी0 सिंह, अध्यक्ष, यू0जी0सी0 द्वारा वेबिनार के सम्बन्ध में अपने उद्‌गार व्यक्त किये गये।
- प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुये वेबिनार के विविध तकनीकी सत्रों में हुये विचार–विमर्श एवं प्रस्तुतीकरण द्वारा उभरकर आये प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराया गया।
- मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 द्वारा ऑनलाईन सत्र में सम्मिलित होते हुये मा0 आयुष मंत्री, भारत सरकार, पूर्वान्चल विकास बोर्ड के मा0 उपाध्यक्षगण, मा0 सलाहकार, मा0 सदस्यगण, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति, प्रमुख सचिव नियोजन, मा0 सांसदगण, शिक्षाविदों तथा अन्य उपस्थित प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए अपने उद्‌बोधन में **निम्न मार्गदर्शन प्रदान किये**:–

  - पूर्वान्चल क्षेत्र में अयोध्या, काशी, प्रयागराज जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विद्यमान हैं। यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ है तथा प्रकृति की असीम कृपा से लगभग सभी स्थानों पर जल भी मीठा है। अतः हमें इस पिछड़ेपन वाली सोच से ऊपर उठकर अपने विकास के लिए स्वयं ही सतत् प्रयास व संघर्ष करते रहना होगा।
  - स्थानीय समस्याओं का हर हाल में स्थानीय स्तर पर ही समाधान होना चाहिए इसके लिए स्थानीय संस्थाओं यथा–विश्वविद्यालय, कालेज, टेक्निकल संस्थानों को एक साथ जोड़कर स्थानीय समस्याओं का समाधान एवं निराकरण करना होगा।
  - गोरखपुर विश्वविद्यालय में तीन दिनों के मंथन के बाद जिन समस्याओं की पहचान की गई है, उनका स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया जाना चाहिए। स्थानीय संस्थान, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थान, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिछले तीन वर्षों में इंसेफलाइटिस को नियंत्रित करने के समन्वित प्रयासों के राज्य के अनुभव ने वैश्विक महामारी कोरोना को नियंत्रित करने में मदद की है। इन अनुभवों के आधार पर, हमें पूर्वांचल के सतत् और समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिसमें सभी संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और एक समन्वित योगदान करना होगा।
  - प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों को कृषि विश्वविद्यालय से जोड़ना है। विकासखण्ड स्तर पर किसान उत्पादक संघ स्थापित करके कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

- बौद्ध टूरिज्म को पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे विश्व में स्थापित किया जा सकता है। इन टूरिज्म स्थानों पर होटल रेस्टोरेंट, ओला–उबर आदि पर काम करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना होगा।
- सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आदि सहित प्रदेश के सभी जनपदों में विकास कार्य कर रही है। पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे पूर्वी क्षेत्र के विकास की बैकबोन बनने जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र के युवाओं को वहीं पर रोजगार देना होगा।
- अधिकांश युवाओं को सरकार की बहुत सी योजनाओं की जानकारी नही है। अतः तकनीकी संस्थानों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी युवाओं को प्रदान करनी चाहिए।
- शासन द्वारा कोई भी घोषणा/योजना लागू होती है तो वह अधिकांश लोगों को मालूम नहीं हो पाती है। अतः शासन की नीतियों के बारे में हमें अपने संस्थानों के माध्यम से लोगों को और युवाओं को अवगत कराना चाहिए।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से व्यापक बदलाव होने वाला है। सभी संस्थानों को नेशनल एजूकेशन पालिसी को लेकर एक समिति का गठन करना चाहिये जो नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में काम करे।
- ''एक जनपद एक उत्पाद'' योजना के माध्यम से प्रत्येक जनपद को अपने विशेष उत्पादों को और विकसित करना होगा।
- प्रदेश के 38 जनपद जापानी इन्सेफ्लाईटिस से प्रभावित थे। जापानी इन्सेफ्लाईटिस की बीमारी पर प्रदेश सरकार की क्रियान्वित रणनीति से इसे नियंत्रित करने में सफलता मिली है, जिसकी सराहना डब्लू0एच0ओ0 द्वारा भी की गयी।
- पूर्वान्चल विकास बोर्ड, नियोजन विभाग एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को इस राष्ट्रीय वेबिनार में मिले सुझावों को प्रदेश के सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सकारात्मक सोच के साथ विभागीय कन्वर्जेन्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा।

राष्ट्रीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- राष्ट्रीय वेबिनार–सह–संगोष्ठी की पूरी अवधारणा को पांच क्षेत्रों – प्राथमिक, सामाजिक, सेवा, विनिर्माण एवं जल के साथ–साथ सात विशेष सत्रों यथा–औद्योगिक विकास, बैंकर्स मीट, विशेष संगठित समूह, पूर्वांचल के लिए विशेष पैकेज, खेलकूद अनुसंधान, पूर्वांचल में विकास और उद्यमशीलता में विभाजित किया गया था। वेबिनार की अवधि में सभी सेक्टरों में कुल 56 सत्र आयोजित हुये। इन तकनीकी सत्रों में हुये विचार–विमर्श/प्रस्तुतीकरण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर आयेः–

  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा सहायतित "कृषि अवस्थापना सुविधा" का अनुकूलतम उपयोग किये जाना।
  - कृषि एवं इससे जुड़ी श्रम शक्ति पर फोकस करना।
  - हर्बल उत्पादों को अपनाया जाना।
  - सब्जी की खेती स्थानीय आवश्यकतानुसार कराये जाना।
  - बैंकों के माध्यम से कृषकों को आसानी से लोन दिलाना।
  - महाराष्ट्र राज्य की तरह प्याज की खेती कराना।
  - आम उत्पादन तथा नींबू की बागवानी कराना।
  - खाड़ी देशों में हरी मटर, मिर्ची के निर्यात के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि कराना।
  - मत्स्य पालन में आ रही विविध समस्याओं यथा– तालाबों की खराब स्थिति, जल संसाधन का कम उपयोग आदि को दूर करना।
  - वियतनामी मूल की "पैंगिसयस" मछली की विशेषता व उसके व्यवसाय से आय वृद्धि के सम्बन्ध में जानकारी का प्रसार कराना।
  - पूर्वांचल के 11 जनपदों को आई0आई0ए0आर0 के सहयोग से "काला नमक चावल" योजना से आच्छादित कर निर्यात प्रोत्साहन पर बल देना।
  - गुजरात पैटर्न पर दुग्ध उद्योग का विकास किये जाना।
  - खाद्य सामग्रियों के पैकेजिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं इनोवेशन पर विचार करना।
  - वैश्विक एवं भारतीय परिपेक्ष्य में सजावटी मछली से होने वाले लाभ तथा इसकी प्रजाति के विस्तार करने पर बल देना।
  - कदन्त में मौजूद पोषक तत्वों से आधुनिक बीमारियों से निजात पाने में मदद मिलने के परिप्रेक्ष्य में कदन्त बेकरी उत्पाद प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाना।

- पारम्परिक उच्च गुणवत्ता के चावल को प्रीमियम इनकम जनरेंटिंग राइस में परिवर्तित करके कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) को नई सोच, तकनीकी एवं पारदर्शिता के साथ सुदृढ़ करते हुए कप्यूटराइजेशन कर बहुआयामी बनाने तथा एफ0पी0ओ0 को मजबूत करने पर जोर दिया जाना।
- आर्गेनिक खेती की सहायता से पूर्वान्चल को उत्पादन, विपणन तथा निर्यात सेक्टर में "हब" बनाने पर बल दिया जाना।
- "खुशबूदार फसलों (ऐरोमेटिक क्राप्स)" की खेती से कृषकों की आय में वृद्धि किया जाना।
- आलू कृषकों द्वारा उत्पादित आलू के उन्नत बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित कराना।
- बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पौधों की प्रजाति पर फोकस करने पर बल देना।
- कृषि मार्केटिंग को विकसित करने हेतु तकनीकी सुधार तथा किसानों को प्रशिक्षित करने पर बल देना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में पशु उत्पादन कम होने के कारण इसको प्रोत्साहन देना तथा टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा पर बल देना।
- पोल्ट्री व्यवसाय के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर की इकाई बढ़ाने, पशुओं का बीमा कराने तथा चारे की समस्या दूर करने हेतु चारागाह के क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार करना।
- एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के अन्तर्गत हैण्डलूम उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु हैण्डलूम उद्योग को बढ़ावा देना।
- पूर्वी क्षेत्र के वाटर प्रोन एरिया (Water Prone Area) होने के परिप्रेक्ष्य में मिनरल वाटर प्लान्ट की स्थापना पर विचार करना।
- पूर्वी क्षेत्र के जनपदों यथा– अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मिर्जापुर के उत्पादों को प्रोत्साहन तथा निर्यात में बढ़ावा दिये जाने पर बल देना।
- बायो, मेडिकल एवं कंस्ट्रक्शन वेस्ट के उपयोग हेतु वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेन्ट पर बल देना।
- फल एवं सब्जियों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को एम0एस0एम0ई0 के अंतर्गत स्थापित किये जाना।
- ''वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'' के अंतर्गत तैयार किये जा रहे विविध उत्पादों यथा–हैण्डलूम, कारपेट, हैण्डीक्राफ्ट, हार्डवेयर इत्यादि की पैकेजिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी मेन्टेन करने हेतु कामन फैसेलिटीज सेन्टर/वेयर हाउस स्थापित किये जाने पर विचार करना।

- पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अतिरिक्त सोलर ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया जाना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सालिड वेस्ड मेनेजमेंट एवं एफ्लूएंट ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट की स्थापना पर विचार करना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में एअर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किये जाना।
- पूर्वान्चल में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए रोड नेटवर्क का निर्माण किया जाना।
- राजस्व ग्रामों में दोहरी कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर विचार करना।
- लोक निर्माण विभाग को छोड़कर सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्य निर्माण एजेन्सियों द्वारा लोक निर्माण के मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण कार्य कराये जाने की व्यवस्था/नीति बनाने पर विचार करना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र विशेषकर गोरखपुर में टेराकोटा प्रोडक्ट से सम्बन्धित इण्डस्ट्रीज को ओ0डी0ओ0पी0 के तहत प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता होना।
- एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत उद्यम स्थापित किये जाने हेतु शिक्षित व कुशल व्यक्तियों को आधुनिक तकनीक, संसाधन व अन्य व्यवस्थाओं पर जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होना।
- पूर्वान्चल सहित उत्तर प्रदेश में वर्तमान रोजगार की स्थिति मुख्य रुप से कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र में होने के दृष्टिगत भविष्य में कौशल विकास हेतु आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, इन्टरनेट आफ थिंग्स, ब्लाक चेन, साईबर सिक्योरिटी, 5जी कम्युनिकेशन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाये जाने पर विचार करना।
- महिलाओं के विकास हेतु उन्हें तकनीकी शिक्षा दिलाये जाने पर बल देना।
- निजी क्षेत्र के सहयोग से धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को बेहतर यातायात सुविधा देकर विकसित करना।
- अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी को ''गोल्डेन ट्राईऐंगिल स्पीरिचुअल'' टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाना।
- पूर्वान्चल में राष्ट्रीय धरोहरों के साथ पंचकोसी यात्रा, सलखन फासिल पार्क (सोनभद्र) तथा प्रागैतिहासिक शैल चित्र, लखनिया पेंन्टिग आदि के संरक्षण की आवश्यकता होना।
- व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे नयी शिक्षा नीति से जोड़ने पर विचार करना।
- विद्युत चालित वाहनों के विकास की सम्भावनाओं पर विचार करना।

- अधिग्रहित भूमि के सुनिश्चित उपयोग, भूमि सम्बन्धित विवादों का निपटारा, किरायेदारों के सम्बन्ध में लीज का पुर्नमूल्यांकन, प्लास्टिक के उन्मूलन, नगर निगम क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण एवं तत्सम्बन्धी जैविक खेती जैसे नवोन्मेषी विचारों को अपनाया जाना।
- नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने पर विशेष बल देना।
- वाहन निरीक्षण कार्यक्रम, गाड़ी फिटनेस सेन्टर एवं ड्राईवर फिटनेस को प्रोत्साहित करना।
- फाइबर टू द होम तकनीक के विकास से टेलीकॉम आपरेटर्स के आय के स्रोतों को बढ़ाना तथा संचार सेवाओं की लागत को वहनीय बनाया जाना।
- दिहाड़ी मजदूरों को निकटस्थ बाजारों में नियमित रोजगार न मिल पाने के परिप्रेक्ष्य में लेबर हायर एप्लिकेशन को विकसित करने पर बल दिया जाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार, डिजिटल जागरूकता और क्रेडिट बाजार के बेहतर क्रियान्वयन के लिये आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के उपयोग पर विचार करना।
- सीमान्त एवं निम्न आय वर्ग के लोगों की वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में तेजी लाने के लिये संरचनात्मक एवं एकीकृत प्रयास किया जाना।
- वेक्टर और जल जनित रोगों और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।
- SARS, COVID-19 और उनके नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता कराना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।
- एम0बी0बी0एस0 जैसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने स्तर से बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कालेजों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन, संविदा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, एम0आर0 और जूनियर रेजिडेंट की स्टाइपेंड में वृद्धि आदि पर विचार करना।
- स्मार्ट क्लासेस सिस्टम तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों पर छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु बल दिया जाना।
- परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की उपस्थिति और महिला शिक्षकों की उपलब्धता पर ध्यान दिये जाना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में शैक्षिक सुधारों को लागू करने तथा सकल नामांकन दर को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होना।
- पूर्वान्चल क्षेत्र में छात्र–शिक्षक अनुपात में सुधार हेतु प्रयास करना।
- महिला साक्षरता दर में वृद्धि हेतु प्रयास करना।

- नियोक्ता और श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखकर स्थानीय स्तर पर नये नवाचार को बढ़ावा देना।
- खाना पकाने का तेल, बायोडीजल का एक सम्भावित क्षेत्र होने के परिप्रेक्ष्य में इसके उत्पादन के व्यवसायीकरण के लिए प्रयास करना।
- 'विटामिन–ए' के स्रोत के रूप में गोल्डन स्वीट पोटैटो की खेती के लिये जागरूकता लाना।
- पुरानी सिंचाई प्रणाली को बदलने, नदियों के बहाव को नियंत्रित करने हेतु चैनलाइजेशन, सिल्ट वेन/बॉटम पैनल इत्यादि कार्य किये जाने एवं उच्च उत्पादकता वाली फसलों हेतु अधिक पानी की आवश्यकता तथा नहरों के माध्यम से असमान जल वितरण से सम्बन्धित बिन्दुओं के समाधान पर विचार करना।
- मौसम के अनुसार जल की गहराई में परिवर्तन तथा औद्योगिक कचरों से युक्त पानी को सीधे नदी में गिराने आदि के निराकरण के सम्बन्ध में प्रयास करना।
- विन्ध्यांचल क्षेत्र के वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु बड़े बांध बनाने पर विचार करना।
- गंडक, शारदा सहायक प्रणाली में बनी हुई संरचनाओं की पुनरोद्धार की आवश्यकता होना।
- हिमालय से निकलकर पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाली नदियों से सिल्ट की समस्या का निराकरण कराना।
- सिंचाई एवं बाढ प्रबन्धन में पूर्व निर्मित संरचनाओं का आधुनिकीकरण किया जाना।
- रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन पर बल देना।
- जल संरक्षण नीति की आवश्यकता।
- बाढ़ के प्रभाव को कम करने हेतु उपाय कराना।
- पुरानी पाइप लाइनों से जल के ह्रास होने के परिप्रेक्ष्य में इनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता।
- भूमिगत जल का दोहन प्रबन्धन।
- पर्यावरण के सम्बन्ध में जनमानस में जागरूकता।
- दूषित जल को पारम्परिक तकनीक द्वारा साफ करने की आवश्यकता।
- भूजल में आर्सेनिक की समस्या तथा भूजल स्तर में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में पूर्वान्चल के समस्त विकासखण्डों में मल्टीपल मानीटरिंग नेटवर्क की आवश्यकता होना।
- कम गहराई में लगे पम्पों को ठीक कराया जाना।
- पेयजल से आर्सेनिक की मात्रा दूर करने के लिए चिन्हित ग्रामों में फिल्टर उपलब्ध कराने पर विचार करना।
- औद्योगिक कचरे के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था कराना।

- गंगा नदी के किनारे दाह संस्कार स्थलों को विकसित कराना।
- अधिक पेड़ लगाये जाने, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट तथा वाटर रीयूज एण्ड रीसाइक्लिंग की आवश्यकता होना।
- जल के उपभोगकर्ताओं के मध्य संतुलित वितरण हेतु डेटा बेस तैयार करना।
- जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रोत्साहन देना।
- स्वच्छता प्रबंधन हेतु सहयोग प्रदान करना।
- भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन पर विचार करना।
- उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले जल के नियंत्रण पर विचार करना।
- स्वच्छ जल हेतु Nano Tulee Filteration का उपयोग।
- पूर्वान्चल में बाढ़ एवं सूखे की समस्या के निदान हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता होना।
- वाटर क्वालिटी टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं रेवन्यू सुविधाओं को डिजिटाइज्ड करने की आवश्यकता।
- अटल मिशन फार रेजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन की गाइड लाइन्स का पालन कर अप्रेजल और गैप असेसमेन्ट को ज्ञात करके इसके निदान हेतु स्थानीय लोगों की सहभागिता की आवश्यकता।
- सभी परिवारों के आवास में स्थित शौचालयों को सीवर से जोड़ने हेतु सम्बन्धित अथारिटी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रबन्ध किये जाने पर विचार करना।
- सिंचाई तकनीक की नई पद्धतियों का उपयोग करके आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता।
- ''इन्टीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट'' में ब्राजील और फ्रांस के माडल को एडाप्ट करने की आवश्यकता पर विचार करना।
- इरीगेशन मैनेजमेन्ट पर फ्रांस के माडल को एडाप्ट करने की आवश्यकता पर विचार करना।
- टेराकोटा आइटम को विभिन्न स्थलों तक ऑनलाईन पहुंचाने के लिये पैकेजिंग की समस्या के निराकरण पर विचार करना।
- केले के पेड़ को कचरे में बदलने व केले से फाइबर तैयार करने विषयक तकनीक को प्रोत्साहन देना।
- पूर्वांचल क्षेत्र में विशेष समूहों के लिए जनसुविधा केन्द्रों एवं स्वंयसेवी संगठनों को बढ़ाने की आवश्यकता।
- छोटे एवं मध्यम उद्योगों के कारीगरों के जीवन में व्यापक आर्थिक एवं सूक्ष्म स्तर की समस्याओं का समाधान।

- आधारभूत संरचनागत प्रबन्धन में 3D मैपिंग और जी0आई0एस0 तकनीक के उपयोग पर विचार करना।
- सरकारी विशेष आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ को वृहद स्तर पर लागू किये जाने की आवश्यकता होना।
- स्वयं सहायता समूहों का बैंकों द्वारा खाता खोले जाने, बैंकिग समिति बनाकर लोगों को साक्षात्कार के माध्यम से लोन देने पर बल देना।
- किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्टार्टअप कार्यक्रम को डिजीटाइज करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता होना।
- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अधिक से अधिक उद्यमियों को आच्छादित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पी0एम0रोजगार योजना एवं पी0एम0 किसान योजना में रोजगार के अवसर को बढ़ाना।
- जन सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं में छोटे–छोटे खाते खोले जाने, वन–टाइम सहयोग प्रदान कर पुनः लोनिंग करने तथा के0सी0सी0 का शत–प्रतिशत संतृप्तीकरण हेतु डिजिटल पोर्टल लान्च करने पर बल देना।
- स्टार्ट–अप के लिए विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान देना।
- हथकरघा की परंपराओं को बनाए रखने के लिए 'लोकल फॉर वोकल' की आवश्यकता।
- पारंपरिक उत्पादों के लिए नए डिजाइन विचारों को विकसित करने तथा स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की आवश्यकता।
- 4 M's यानि मैन, मनी, मशीन और मार्केट का क्लस्टर बनाने की आवश्यकता।
- 'रिवर्स माइग्रेशन' को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां और रणनीतियाँ।
- उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कुशल मानव–संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधा की आवश्यकता।
- विश्व स्तर के होटल, हवाई अड्डे और प्राथमिक और उच्च शिक्षा केंद्र विकसित करने के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता।
- अत्याधुनिक अनुसंधान, परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता।
- पूर्वांचल को आई0टी0 हब के रूप में विकसित करना।
- कई SEZs विकसित करने पर विचार करना।
- भूमि बैंक विकसित करने के लिए औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता।
- विश्वविद्यालयों में खेल विभाग न होने, योग्य प्रशिक्षकों और शिक्षकों की भारी कमी तथा वित्तीय व्यवस्था का अभाव होने के परिप्रेक्ष्य में इनके निराकरण हेतु प्रयास करना।

- पूर्वांचल के 28 जिलों में स्टार्टअप और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एक साल में 1000 स्टार्टअप्स की योजना के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड के सहयोग से दीनदयाल

उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है।

- आई0आई0एम0एस0 की देख–रेख और मार्गदर्शन में उद्यमिता विकास संस्थान, गांधीनगर की सहायता से उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए, जिसे गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में एक साथ शुरू किया जा सकता है।
- गोरखपुर और वाराणसी में कम से कम दो कौशल विकास केंद्र स्थापित करके पूरे पूर्वांचल के कौशल को पेश करने का प्रयास किया जा सकता है।
- वित्त मंत्री द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र के लिए बैंकरों से रू0 40,000 करोड़ के विशेष फंड की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया।
- पूर्वांचल क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज के आयोजन पर विचार किया जा सकता है।
- नई शिक्षा नीति–2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
- गोरखपुर से मॉडल शहर के रूप में शुरू होने वाले बायो प्रबंधन (बायोडिग्रेडेबल और गैर–बायोडिग्रेडेबल) के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।
- ओ0डी0ओ0पी0 को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की स्थापना के लिए प्रयास शुरू किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार और खेलो इंडिया के सहयोग से गोरखपुर और वाराणसी में दो सर्वश्रेष्ठ खेल केंद्रों की स्थापना करके ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नर्सरी के लिए पूर्वांचल के जिलों में विशेष प्रतिभा खोज खेल कार्यक्रम, फेलोशिप और खेल संस्कृति की शुरूआत किया जाना चाहिए। यह पर्याप्त खेल प्रतिभा और प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित होना चाहिए।
- जनपदों में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों को कृषि विश्वविद्यालय से जोड़ना चाहिए।
- विकासखण्ड स्तर पर किसान उत्पादक संघ स्थापित करके कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जानी चाहिए।
- बौद्ध टूरिज्म को पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे विश्व में स्थापित किया जा सकता है। इन टूरिज्म स्थानों पर होटल रेस्टोरेंट, ओला–उबर आदि पर काम करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए।
- अधिकांश युवाओं को सरकार की बहुत सी योजनाओं की जानकारी नही है। अतः तकनीकी संस्थानों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी युवाओं को प्रदान करनी चाहिए।

परिशिष्ट

राष्ट्रीय वेबिनार
श्री योगी आदित्यनाथ, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का उद्‌बोधन

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं। इन जनपदों की आर्थिक व भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में मुख्यतः 04 आर्थिक संभाग यथा–पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय व बुंदेलखण्ड हैं। प्रदेश के इन आर्थिक सम्भागों की जहाँ एक ओर अपनी–अपनी विशिष्टतायें हैं, वहीं दूसरी ओर इन सम्भागों की अपनी–अपनी समस्यायें भी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्वी सम्भाग के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा परामर्शी संस्था के रूप में पूर्वान्चल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सहयोग से इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है।

पूर्वी सम्भाग की वर्तमान प्रास्थिति

प्रदेश का पूर्वी सम्भाग कला, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, कृषि कर्म व वैभवशाली इतिहास से परिपूर्ण है। यह सम्भाग प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला से सम्पन्न है और इसकी समृद्ध पुरातात्विक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। नदियों और उनकी सहायक नदियों (गंगा, घाघरा, राप्ती, यमुना, सोन, गोमती) की बाहुल्यता ने इस सम्भाग में समृद्धि सुनिश्चित की है और नदियों के घाटों ने समय–समय पर धार्मिक/ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों के विकास के लिए मंच प्रदान किया है। यह भगवान राम, गौतम बुद्ध, महावीर और अन्य जैन तीर्थंकरों की भूमि है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति इसी क्षेत्र की देन मानी जाती है। कई महत्वपूर्ण धर्म इस क्षेत्र और उनके तीर्थों, पवित्र तीर्थ केंद्रों और स्मारकों के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था जो प्राचीन काल में इसका एक बड़ा हिस्सा था। प्रयागराज और वाराणसी (काशी) दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में माने जाते हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थलों में आते हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास होने के उपरान्त भी यह सम्भाग आज के विकासात्मक युग में सापेक्षिक रूप से अल्प विकसित है। इस क्षेत्र का अपेक्षाकृत सामाजिक और आर्थिक विकास कम होना, प्रति व्यक्ति आय न्यून होने तथा जी0एस0डी0पी0 की विकास दर धीमी है।

पूर्वी सम्भाग के अंतर्गत 28 जनपद आते हैं। इस सम्भाग का भौगोलिक क्षेत्रफल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 36 प्रतिशत है, जहाँ प्रदेश की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 77.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है जबकि इस क्षेत्र की 87.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, अर्थात् इस क्षेत्र में नगरीकरण का स्तर प्रदेश के औसत से कम है।

प्रति व्यक्ति आय

प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वर्ष 2018–19 में रु0 66512 आंकलित की गई है। इसी अवधि में पूर्वी सम्भाग की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रु0 44304, पश्चिमी सम्भाग की रु0 91445, केन्द्रीय सम्भाग की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रु0 63540 तथा बुन्देलखण्ड सम्भाग की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रु0 68363 रही है। स्पष्ट है कि पूर्वी सम्भाग की प्रति व्यक्ति आय प्रदेश के औसत के साथ–साथ अन्य सम्भागों से कम है।

कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र

पूर्वी सम्भाग में काली मिट्टी, मटियारी, दोमट, चिकनी, बलुई दोमट तथा काली दोमट मिट्टी पायी जाती है। पूर्वान्चल क्षेत्र की मिट्टी समृद्ध गुणवत्ता व उच्च केंचुआ घनत्व के कारण कृषि के अनुकूल है। यह पाया गया है कि पूर्वी सम्भाग में अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के अधीन है, परंतु सभी प्रमुख फसलों का उत्पादन राज्य औसत और अन्य सम्भागों की तुलना में कम है। प्रदेश के अन्य सम्भागों की तुलना में पूर्वी सम्भाग में संसाधनों की कमी, परंपरागत कृषि पर अधिक निर्भरता, लघु जोतें होने के कारण कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का अपेक्षाकृत विकास कम हो पाया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश जल संपदा के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश जनपद नेपाल की तराई तथा गंगा, घाघरा, राप्ती नदियों के बेसिन में स्थित होने के कारण इस सम्भाग में जलप्लावित क्षेत्र तथा नदियों के बैक वाटर झीलों के रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें ग्राम सभा के स्वामित्व के साथ–साथ स्थानीय निवासियों के भी स्वामित्व की जमीन सम्मिलित है। इस क्षेत्र में मत्स्य पालन की अपार सम्भावनायें हैं।

अवस्थापना सुविधाएं

परिवहन एवं संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने के लिये सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों एवं जल मार्गों का विकास किया जाना आवश्यक है। कृषि एवं औद्योगिक विकास, परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रियाकलापों, कच्चे माल की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये सड़क एवं अन्य परिवहन के माध्यमों का विकास एवं विस्तार बहुत जरूरी है।

परिवहन के विभिन्न साधनों के मध्य सड़क परिवहन अपनी लास्टमाइल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है। पूर्वान्चल का क्षेत्र, सड़कों के मामले में समृद्ध है। सड़क परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में 341 कि0मी0 लम्बाई का पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे एवं 91.352 कि0मी0 लम्बाई का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे निर्मित कराया जा रहा है।

पूर्वी सम्भाग के अधिकांश जनपद तराई क्षेत्र में स्थित हैं जहाँ के मार्ग प्रति वर्ष बाढ़/अतिवृष्टि तथा वाटर टेबुल ऊपर होने के कारण अपेक्षाकृत ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं।

कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में अभिवृद्धि करने के साथ ही हमारे दैनिक जीवन की समृद्धि के लिये विभिन्न उपकरणों के प्रयोग में विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वी सम्भाग में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 268.56 किलो वाट आवर है जो प्रदेश के अन्य सम्भागों से कम है।

उद्योग

औद्योगीकरण किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें उद्योग शामिल है, का प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2018–19 में 14.54 प्रतिशत योगदान रहा है, वहीं पूर्वी सम्भाग में इसका योगदान 7.01 प्रतिशत है। अतः पूर्वी सम्भाग औद्योगीकरण के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़ा है।

बैंकिंग एवं वित्त

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योग व व्यापार के विकास में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बैंक नए पूंजी निर्माण में सहायता प्रदान करते हुए क्षेत्र के आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। प्रदेश के पूर्वी संभाग में बैंकिंग सेवाओं का प्रसार प्रदेश के औसत से कम है। एक ओर जहां, पूर्वी सम्भाग का ऋण–जमा अनुपात 29.69 है, वहीं प्रदेश का औसत 42.25 है।

शिक्षा

सभी अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं कि शिक्षा या मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अर्थशास्त्रीय अध्ययन साक्ष्य प्रदान करते हैं कि अधिक शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादक होते हैं और वे उच्च वेतन अर्जित करते हैं। शिक्षा और राष्ट्रीय आय का औसत स्तर एक साथ बढ़ता है। इस प्रकार शिक्षा, आर्थिक विकास प्रक्रिया में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.68 प्रतिशत थी जबकि पूर्वी सम्भाग की कुल साक्षरता दर 67.40 प्रतिशत थी। स्त्री–पुरुष साक्षरता दर में अंतर प्रदेश स्तर पर 20.10 प्रतिशत के सापेक्ष पूर्वी सम्भाग में 21.88 प्रतिशत था। राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2016 में प्रदेश की साक्षरता दर 77.1 प्रतिशत पहुँच गयी है जबकि पूर्वी सम्भाग की साक्षरता दर वर्ष 2016 में 78.8 प्रतिशत हो गयी है, जो प्रदेश के अन्य सम्भागों से बेहतर है।

श्रम

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 32.94 प्रतिशत कर्मकर हैं जबकि पूर्वी सम्भाग में यह 33.04 प्रतिशत है। पूर्वी सम्भाग के कुल कर्मकरों का 34.60 प्रतिशत मुख्य कृषक तथा 24.82 प्रतिशत मुख्य कृषि श्रमिक हैं। प्रदेश स्तर पर यह औसत क्रमशः 34.90 प्रतिशत तथा 21.84 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि पूर्वी सम्भाग में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत प्रदेश औसत से अधिक है। अर्थात् पूर्वी सम्भाग में कृषि से जुड़े कर्मकरों की अधिकता होने के उपरान्त भी उनकी उत्पादकता कम है।

पर्यटन

पूर्वान्चल क्षेत्र में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, विंध्याचल, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशांबी, सारनाथ आदि क्षेत्र के महत्वपूर्ण पवित्र एवं सांस्कृतिक स्थल हैं।

भावी रणनीति

- पूर्वी सम्भाग के विकास और अंतर्जनपदीय विषमता की समस्या को दूर करने के लिए बहु–आयामी रणनीति की आवश्यकता है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्रिय नीतियां, सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक सार्वजनिक व्यय और कृषि और औद्योगिक उत्पादन के विकास के लिए विशिष्ट क्षेत्र को शामिल करना चाहिए।
- विकास योजनाओं के निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर के साथ–साथ जिला स्तर पर नियोजन मशीनरी को प्रभावशील बनाया जाए। साथ ही साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए समावेशी योजना का निर्माण किया जाए।
- पूर्वी सम्भाग में गवर्नेंस पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि गवर्नेंस और सेवा वितरण में सुधार हो और निजी निवेश आकर्षित हो सके।

- इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
- क्षेत्र के ग्रामीण–शहरी विभाजन, डिजिटल विभाजन, अंतर्जनपदीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपयुक्त वित्तीय और वितरण तंत्र के साथ नई योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश के पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों की वृहद स्तरीय समस्याओं को हल करने के लिए फसलों, पशुधन, बागवानी, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन, कृषि प्रसंस्करण, फसल उपरांत प्रबंधन आदि से संबंधित समग्र प्रणाली के दृष्टिकोण को लागू किये जाने की आवश्यकता है। कृषि में विविधता हासिल किए जाने के लिए, सड़कों और बिजली के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे यथा– बाजार एवं ग्रेडिंग सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज निर्माण आदि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। कृषक उत्पादक समूह के गठन को बढ़ावा दिया जाये जिससे कृषकों को उनके कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।
2. प्राकृतिक, जैविक एवं जीरो बजट कृषि के प्रमाणीकरण एवं नियम को सरल किया जाए तथा इसका वृहद स्तर पर तकनीकी विकास, प्रचार–प्रसार एवं इसके विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूर्वान्चल क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है।
3. क्षेत्र के पारंपरिक फलों जैसे आम, अमरूद, लीची, केला आदि के अतिरिक्त नए फलों जैसे– ड्रैगन फ्रूट, अंजीर, एप्पल बेर, स्ट्रॉबेरी, कीनू आदि की खेती को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही केले की खेती को बढ़ावा देने हेतु पूर्वान्चल के जनपदों में टिशू कल्चर लैब हार्डेनिंग हेतु नेट हाउस की स्थापना की जाए।
4. वर्तमान में मोटे अनाजों की उपयोगिता को देखते हुए मडुवा या रागी व सावां की खेती को बढ़ावा दिया जाए।
5. पूर्वी सम्भाग जो बाढ़ और अतिवृष्टि, जल निकासी प्रणाली की समस्याओं से ग्रस्त है, में विशेष बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
6. कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा खाद्य सुरक्षा एवं कृषकों के सामूहिक विकास के लिए फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज, क्लस्टर आधारित व्यापारिक संरचनाएं एवं उत्पादक समूह के माध्यम से छोटे एवं सीमांत कृषको के जीवन यापन के मूलभूत संसाधनों को विकसित किए जाए।
7. उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों, शोध संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों,कस्टम हायरिंग केंद्रों आदि का समुचित विकास किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों से समन्वय

स्थापित कर नवीनतम तकनीकों एवं प्रबंध प्रणालियों का प्रशिक्षण क्षेत्र के कृषि एवं संवर्गीय व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को दिया जाना जरूरी है।

8. ग्राम सभा के तालाबों के लिए निवेश यथा–उच्च कोटि के मत्स्य बीज एवं आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मत्स्य पालकों का मत्स्य पालन के नवीनतम तकनीकों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए।
9. जनपद और विकास खण्ड, दोनों स्तरों पर ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र (Rural Economic Zones) स्थापित किए जाने चाहिए, जो आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे।
10. पूर्वी सम्भाग में कुछ गलियारों या क्षेत्रों की पहचान कर उनमें बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए जिससे कि इस क्षेत्र की औद्योगिक समृद्धि को निजी सार्वजनिक भागीदारी की सहायता से प्रोत्साहन दिया जा सके।
11. प्रयागराज, वाराणसी जैसे नए स्थानों में कुछ बड़े आई0टी0 आधारित एस0ई0जेड0 स्थापित करने हेतु प्रगतिशील और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।
12. पर्यटन क्षेत्रों, महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन इकाईयों, महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों आदि के लिए सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी जाये। नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हवाई पट्टी विकसित की जाए।
13. उद्योग की स्थापना हेतु आधारभूत सुविधाओं यथा–निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सड़क, औद्योगिक भूमि इत्यादि की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए जिस हेतु यथावश्यकता तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को स्थापित उद्योगों के सहयोग से संचालित किये जायें जिससे ट्रेड विशेष में कुशल एवं प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध हो सके।
14. वन टांगिया एवं मुसहर बस्तियों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर नवीन विद्यालय की स्थापना एवं शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
15. विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ ही समय–समय पर छात्रों के लर्निंग आउटकम का आंकलन किया जाए तथा पिछड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
16. शिक्षकों के पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण एवं नवाचार गतिविधियों से परिचित कराए जाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्हें शिक्षा के नवीनतम तकनीक का ज्ञान प्रदान किए जाने हेतु कार्यशाला अथवा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कराये जाए।
17. व्यवसायिक तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय उद्योग की आवश्यकतानुसार रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जाए।
18. चिकित्सालयों में मानक के अनुसार डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाए। साथ ही चिकित्सालयों में दवाइयों की उपलब्धता एवं आवश्यक उपकरणों की तथा उनके सुचारु संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

19. अभियान चलाकर 20 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में प्रसव को हतोत्साहित किया जाये तथा दो बच्चों के जन्म के मध्य अंतराल बढ़ाए जाने को प्रोत्साहित किया जाए।
20. शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु व्यवहार परिवर्तन, नवजात शिशुओं के घर पर देखभाल तथा जन्म व बचपन के बीमारियों के एकीकृत प्रबंधन हेतु व्यापक संचार रणनीति तैयार की जाए।
21. इस सम्भाग में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाये। साथ ही थीम आधारित पर्यटन (विशेषकर सांस्कृतिक एवं एडवेन्चर पर्यटन) को बढ़ावा दिया जाये एवं आवासीय तथा होटल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाये। स्थानीय युवक व युवतियों को प्रशिक्षित कर उनका उपयोग गाइड के रूप में किया जाये।

हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले प्रबुद्धजनों द्वारा इसके सर्वांगीण विकास के संदर्भ में ठोस सुझाव एवं रणनीति तैयार करने हेतु संस्तुतियां दी जायेंगी, जो राज्य सरकार को नीति निर्धारण एवं कार्य योजना तैयार करने में सहायक होंगी।

मैं इस वेबिनार की सफलता हेतु अपनी शुभकामनायें देता हूँ।

वेबिनार में उपस्थित मा0 मंत्रीगण

- श्री योगी आदित्यनाथ जी, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0
- श्री केशव प्रसाद मौर्य, मा0 उप मुख्यमंत्री एवं मा0 मंत्री, लोक निर्माण
- श्री श्रीपद नाईक, आयुष मंत्री, भारत सरकार
- श्री सूर्य प्रताप शाही, मा0 मंत्री, कृषि
- श्री सुरेश खन्ना, मा0 मंत्री, वित्त
- श्री दारा सिंह चौहान, मा0 मंत्री, वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान
- श्री रमापति शास्त्री, मा0 मंत्री, समाज कल्याण
- श्री श्रीकांत शर्मा, मा0 मंत्री, उर्जा एवं अतिरिक्त उर्जा स्रोत
- श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मा0 मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग
- श्री आशुतोष टण्डन, मा0 मंत्री, नगर विकास
- डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, जलशक्ति
- श्री सुरेश राणा, मा0 मंत्री, गन्ना विकास
- श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, मा0 मंत्री, पंचायती राज
- श्री अनिल राजभर, मा0 मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण
- श्री अतुल गर्ग, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- श्री सतीश द्विवेदी, मा0 मंत्री, बेसिक शिक्षा
- श्री चौधरी उदयभान सिंह, मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
- श्री विजय कश्यप, मा0 मंत्री, राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण
- श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, मा0 मंत्री, लोक निर्माण

वेबिनार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि/प्रशासनिक अधिकारी/शिक्षाविद्

- श्री रवि किशन, मा0 सांसद, लोक सभा
- श्री जय प्रकाश निषाद, मा0 सांसद, राज्य सभा
- डा0 के0वी0 राजू , आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी
- श्री नरेन्द्र सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वांचल विकास बोर्ड
- डा0 दयाशंकर मिश्र ''दयालु'', मा0 उपाध्यक्ष, पूर्वांचल विकास बोर्ड
- श्री साकेत मिश्र, मा0 सलाहकार, पूर्वांचल विकास बोर्ड
- पूर्वांचल विकास बोर्ड के मा0 सदस्यगण
- श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव
- श्री आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव
- श्री संजय भूसरेड्डो, अपर मुख्य सचिव
- डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव
- श्री नवनीत कुमार सहगल, अपर मुख्य सचिव
- श्री अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव
- श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव
- श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव
- श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव
- श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव
- श्री हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव
- श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव
- श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव

- श्री भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव
- श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव
- श्री आमोद कुमार, प्रमुख सचिव
- सुश्री मनीषा त्रिघाटिया, आयुक्त, राजस्व परिषद
- श्री के0 रविन्द्र नायक, आयुक्त, मनरेगा, उ0प्र0,
- श्री विजय किरन आनन्द, महानिदेशक
- प्रो0 कल्पलता पाण्डेय, कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
- डा0 विजेन्द्र सिंह, कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
- डा0 आर0के0 मित्तल, कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
- डा0 ओमकार सिंह, कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
- प्रो0 जे0पी0 पाण्डेय, कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
- प्रो0 आलोक राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय
- प्रो0 के0एन0 सिंह, कुलपति, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
- प्रो0 रविशंकर सिंह, कुलपति, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
- डा0 दिनेश कुमार यादव, प्राचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज
- डा0 जगदीश सिंह, निदेशक, आई0सी0ए0आर0–आई0वी0ए0आर0
- डा0 एस0के0 सिंह, निदेशक, मत्स्य विभाग
- श्री नरेन्द्र कुमार पटेल, निदेशक, राज्य रेशम बोर्ड
- श्री ए0पी0 श्रीवास्तव, निदेशक, कृषि विभाग
- डा0 आर0के0 सिंह, निदेशक, आई0वी0आर0आई0
- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, आई0आई0पी0आर0

- डा0 अरविन्द कुमार, निदेशक, इण्टरनेशनल राइस रिसर्च इस्टीटच्यूट
- डा0 संजय कुमार, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सीड रिसर्च
- डा0 पंजाब सिंह, पूर्व महानिदेशक, आइ0सी0ए0आर0 एवं सचिव, डी0ए0आर0ई0
- प्रोफेसर शक्ति कुमार, चेयरमैन, सेन्टर फार इकोनोमिक स्टडीज एण्ड प्लानिंग, जे0एन0यू0
- डा0 तनवीर आलम, निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, भारत सरकार
- डा0 शैलेन्द्र सिंह, निदेशक, आई0आई0एम0, रांची
- डा0 बलराम शुक्ला, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडी, शिमला
- प्रो0 भारत दहिया, निदेशक, थम्मासाट विश्वविद्यालय, बैंकाक, थाईलैण्ड
- प्रो0 मनोज कुमार मिश्रा, ब्रिटिश अमेरिकन विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा
- श्री फ्रंक इस्लाम, अध्यक्ष, इनवेस्टमेन्ट ग्रुप, अमेरिका
- डा0 रजनीश मिश्रा, एमिटी विश्वविद्यालय, दुबई
- डा0 शिप्रा सुमन, सेन्टर ऑफ मेडिकल इमेजिंग, यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ लंदन
- प्रोफेसर राकेश सिंह, यूनिवर्सिटी आफ जार्जिया
- डा0 नरेश त्रिखा, पूर्व निदेशक, क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव
- श्री अनिल सिन्हा, सीनियर एडवाइजर, 2030 **WRG**
- श्री विप्लब पाल, निदेशक, भुगरू, एन0जो0ओ0
- डा0 अंबरीश गौड़, फैशन डिजाइन विभाग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर
- श्री दिनेश तिवारी, रिलायन्स जियो, लखनऊ
- श्री अवनिन्द्र सिन्हा, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल
- श्री वी0पी0 अजीतसरिया, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इंडस्टोज, गोरखपुर
- श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष, गैलेण्ट ग्रुप आफ इंडस्टोज, गोरखपुर

- श्री एस0के0 अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इंडस्टोज, गोरखपुर
- श्री उमेश कुमार प्रजापति, टेराकोटा कारीगर
- अन्य विशिष्ट विश्वविद्यालयों / संस्थानों के शिक्षाविद

Hon'ble Chief Minister Uttar Pradesh

Shripad Naik, Hon'ble Minister of State (IC)
for Ayush and MOS Defence

Prof. D.P. Singh, Chairman, UGC

आयोजक:
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

Civil Lines, Gorakhpur-273009 U.P. (INDIA)
+91-551-2201577, +91-551-2340363
+91-551-2330767, +91-551-2340363
registrar@ddugu.ac.in
DDU Information Centre (Contact)
+91-551-2203098